वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी के साथ ही औपचारिक तौर पर बजट छपाई का काम शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा परोसकर इसकी शुरूआत की

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 74 दिनांक:17-07-2024 बुधवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक, केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है

डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठ-भेड़ में अफसर समेत 5 जवान शहीद

जम्मू(ईएमएस)। आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। बीते रोज डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आर्मी का एक अधिकारी भी हमले में शहीद हो गया है। कश्मीर के एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने बयान जारी करके कहा है कि सुरक्षाबलों ने जब मुजाहिद्दीन का तलाशी अभियान शुरू किया तो फायरिंग की गई।

जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। वाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर जवानों के घायल होने की सूचना दी। खुफिया जानकारी के आधार पर जंगल में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया गया था। बीते कुछ सप्ताह से जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षाबल अलर्ट पर हैं। 14 जुलाई को कुपवाड़ा में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिन्हें जवानों ने ढेर कर दिया था।

8 जुलाई को कठुआ में हुए आतंकी हमले में पांच सेना के जवान शहीद हो गए थे। वहीं घात लगाकर सेना के काफिले पर किए गए हमले में कई जवान घायल हो गए थे। कुलगाम में 6 जुलई को कई आतंकियों को मार गिराया गाय था वहीं दो जवान भी शहीद हो गए ते। हाल ही में डोडा में भी मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मारा गया था।

बता दें कि कश्मीर टाइगर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ग्रुप है। 9 जुलाई को कठुआ में हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी आतंकी संगठन ने ली थी। अधिकारियों का कहना है कि डोडा में राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शाम को 7 बजे के बाद देसा जंगल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। यहां आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद जंगल में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 20 मिनट चली मुठभेड़ में अधिकारी समेत चार जवान बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चारों जवानों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक उनकी हालत गंभीर थी। डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है। बताया गया कि यहां तीन से चार आतंकी छिपे हो सकते हैं।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा

उत्तराखंड की ज्योतिपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं। एक के बाद एक कई संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष तथा श्रीदूधेश्वरनाथ मठ मंदिर के श्रीमहंत नारायण गिरि ने ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर जाकर राजनीतिक बयान देने को गलत बताया और कहा कि हिन्दू धर्म परंपरा में शंकराचार्य शीर्ष आसन है तथा उनका काम पूजा पाठ करना है और ऐसे पूज्यपाद का किसी के घर जाकर राजनीतिक बयान देना अनुचित है।

इसके अलावा जगतगुरु परमहंस जी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि निश्चित रूप से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मोटी दक्षिणा मिल गई होगी। इसलिए उन्होंने यह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। कभी-कभी अधिक सम्मान और ज्यादा दक्षिणा पाकर लोग मर्यादा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर वो स्थिति आएगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए बचाने के लिए एकनाथ शिंदे अलग हुए और मुख्यमंत्री हैं।

भाजपा की हार पर, योगी के विरोध में अपने ही लगाने लगे सुर

लखनऊ (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को थोड़ा झटका दे दिया है। सपा-कांग्रेस गठबंधन की ओर से शानदार प्रदर्शन के बाद से योगी सरकार को सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन पहले ही यूपी कार्यसमिति की बैठक में हजारों कार्यकर्ताओं ने मंथन कर नतीजों की वजह जानी और आगामी चुनावों पर फोकस करने पर विचार साझा किया। हालांकि इस बीच भाजपा के मंत्री, विधायक ही नसीहत दे रहे हैं। सहयोगी और मंत्री संजय निषाद के साथ ही विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने नौकरशाही पर सवाल उठाया हैं। इसके पहले विधायक रमेश मिश्र और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने भी फिर सरकार बनने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाया है। बीजेपी एमएलसी सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर सवाल कर दिया है। एमएलसी ने पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनता आप की सरकार से नाराज हो गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन हाजिरी के निर्णय को वापस लेने के साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली पर विचार करने की मांग की है। एमएलसी सिंह ने पत्र में लिखा कि आपको नौकरशाहों की साजिशों से बचना होगा। जनता के मन में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसके लिए नौकरशाह जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों ने जनता को नाराज कर दिया। नौकरशाहों के लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बन गए है। वहीं निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं और ऊपर कमल है। वे मौका पाकर डंस लेते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है।

निषाद ने कहा कि हम सहयोगी दल है। पार्टनर का मतलब होता है कि हम फायदे और घाटे में साथ रहे। आज जब सीटें घटी है, तब हम घाटे में भी बीजेपी के साथ रहने वाले हैं। ये बात सही है कि हार के कारणों पर चिंतन होना चाहिए। कई सारे हार के कारण हैं। इसमें आरक्षण से संबंधित, निषाद पार्टी को सीटें न मिलना सहित कई कारण है।

कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया - अमित शाह

चंडीगढ़ (ईएमएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वो हरियाणा में सत्ता में आती है तो यहां भी ऐसा ही करेगी। एक ओबीसी सम्मान सम्मेलन में शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है। 1957 में ओबीसी आरक्षण के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सालों तक लागू नहीं किया।

अमित शाह ने कहा कि 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इसे पेश किया गया तो राजीव गांधी ने दो घंटे 43 मिनट का भाषण देकर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया।

अमित शाह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ही पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। अमित शाह ने कहा, भाजपा ने देश को पहला सशक्त पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री देने का काम किया है। केंद्र में 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। गृह मंत्री ने ओबीसी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया और कहा कि उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया।

गृहमंत्री ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा, मैं एक-एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं, आंकड़ों के साथ मैदान में आएं।

ज्ञात रहे कि हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। भाजपा यहां अकेले चुनाव लड़ने वाली है। उसकी नजर पिछड़े वर्ग को लुभाने पर है, जिनकी राज्य में 27 फीसदी हिस्सेदारी है। तीन सप्ताह से भी कम समय में अमित शाह का यह दूसरा हरियाणा दौरा है। इससे पहले गृह मंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने किया। आरक्षण के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने टीडीपी के आंध्रप्रदेश में आरक्षण पॉलिसी का जिक्र किया ।

सहनी के पिता की हत्या.....जेडीयू के मंत्री ने ट्रंप के हमले से जोड़ा लिंक

पटना (ईएमएस)। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर के नेताओं ने घटना की निंदा कर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। राजद सहित तमाम विरोधी दलों के नेता बिहार में जंगलराज को लेकर हमलावर हैं। वहीं, एनडीए गुट के जदयू नेता ने हत्याकांड को लेकर पूर्व राष्ट्रपत्ति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ते हुए अजीबोगरीब दलील दे दी है।

जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि घटनाएं होती हैं और घटना से हमें दुख है। अमेरिका में ट्रंप पर गोली चली, लेकिन नीतीश कुमार के रहते अपराधी पकड़ा जाएगा। वहीं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या को दुखद बताकर कहा है कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो भी अपराधी है, उन्हें पकड़ा जाएगा।

बता दें कि आरजेडी ने नीतीश सरकार के इकबाल पर सवाल उठाकर प्रदेश में महाजंगलराज होने का आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी पार्टी दुख की इस घड़ी में मुकेश सहनी के साथ है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता का परिवार सुरक्षित नहीं है, तब बिहार में आम जनता का क्या होगा।

राजद नेता तिवारी ने भाजपा पर हमलावर होकर कहा, ये जंगलराज का राग अलापने वाले एनडीए और बीजेपी के लोग अब चुप क्यों हैं। पीएम और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, ये महाजंगलराज है। वहीं, हत्याकांड पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई हत्याएं हुई हैं।

नीट मामले में सीबीआई ने 02 और को धरा

पेपर चुराने और प्रसारित करने वालों पर सीबीआई का शिकंजा

नई दिल्ली,(ईएमएस)। नीट मामले में शिकंजा कसते हुए सीबीआई ने मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पर झारखंड के हजारीबाग में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के ट्रंक से कथित तौर पर पेपर चुराने का आरोप है।

सीबीआई की कार्रवाई की जानकारी दे रहे अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन दो लोगों की गिरफ्तारियों के साथ ही नीट पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बताया गया कि सीबीआई की टीम ने नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया है। आदित्य पर हजारीबाग में एनटीए ट्रंक से नीट-यूजी पेपर चुराने का आरोप है। जबकि दूसरे आरोपी पंकज कुमार बोकारो निवासी को पटना से गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीबीआई टीम ने राजू सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर पेपर चुराने और अन्य सदस्यों तक पेपर पहुंचाने का आरोप है। उस पर पंकज कुमार की मदद करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। राजू हजारीबाग से गिरफ्तार हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और कथित तौर पर नीट परीक्षार्थियों को ठहराने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराने वाले दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह वही जगह है जहां से बिहार पुलिस ने जले हुए प्रश्नपत्र बरामद कर कार्रवाई की थी। सीबीआई ने इन मामलों में 06 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर,अब स्विगी, जोमैटो से भी कर सकेंगे ऑर्डर

नई दिल्ली(ईएमएस)। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दारू खरीदने के लिए अब आपको ठेके पर जाने की जरूरत नहीं है। स्विगी, जोमैटो और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जल्द ही बीयर, वाइन और लिकर जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। उद्योग अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल सहित कई राज्य इस पहल के लिए पायलट परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारी वर्तमान में शराब की डिलीवरी की अनुमति देने के पक्ष और विपक्ष का आकलन कर रहे हैं। 2020 में स्विगी और ज़ोमैटो ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए गैर-मेट्रो क्षेत्रों में ऑनलाइन शराब वितरण शुरू किया, जब उनका मुख्य व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ था। रिपोर्ट में उद्योग के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, यह बढ़ती प्रवासी आबादी, विशेष रूप से बड़े शहरों में, उन उपभोक्ताओं की बदलती प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखकर किया गया है जो मध्यम मात्रा में अल्कोहल युक्त शराब को भोजन के साथ मनोरंजन के रूप में पीते हैं। साथ ही, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने पारंपरिक शराब की दुकानों से खरीदारी करना और दुकान के सामने के अनुभवों को अप्रिय बताया है। स्विगी के कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष दिनकर वशिष्ठ ने ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मॉडल्स में पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, उम्र की पुष्टि और नियमों का पालन होता है। इसके अलावा, ऑनलाइन तकनीक सरकार और एक्साइज नियमों के अनुसार काम करती है, जैसे समय की पाबंदी, ड्राई डे और जोनल डिलीवरी के नियम, सबकुछ अच्छे से फॉलो होता है।

बढ़ सकता है कारोबार

पब चेन द बीयर कैफे के मुख्य कार्यकारी राहुल सिंह ने कहा, शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी को सक्षम करके, राज्य उपभोक्ता सुविधा को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं और जिम्मेदार और विनियमित शराब वितरण सुनिश्चित करते हुए वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।

कोविड में शुरू हुई थी योजना

रिपोर्ट के अनुसार, घरों तक शराब की डिलीवरी की अनुमति केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शराब की डिलीवरी के लिए अस्थायी मंजूरी प्रतिबंधों के बावजूद सफल रही। खुदरा उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन डिलीवरी के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बिक्री में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान

संगठन के नेता बोले- शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार; हरियाणा सरकार ने कहा- नहीं खोला जाएगा

चंडीगढ़ (ईएमएस)। हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे।

किसानों ने किसान शुभकरण के मौत मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती। वहीं शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन इसको लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 माह का राशन है।

के. कविता की तबीयत बिगड़ी, तिहाड़ जेल से अस्पताल पहुंचाया

नई दिल्ली,(ईएमएस)। शराब मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता की अचानक तबीयत खराब होने के चलते डीडीयू अस्पताल पहुंचाया गया है। वैसे इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि उनकी तबीयत क्यों और कैसे बिगड़ी है और क्या शिकायत है।

जानकारी अनुसार बीआरएस नेता के कविता की तबीयत आज बिगड़ जाने के कारण उन्हें इलाज के लिए डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सूत्र यह नहीं बतला सके कि के कविता को किस तरह की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां बतलाते चलें कि के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जिन्हें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया हैं और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने संरा राहत एवं कार्य एजेंसी को दिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ये सालाना दिया जाने वाला पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा है और साल 2024-25 का पहला ट्रांसफर है। पिछले कुछ सालों में भारत 35 मिलियन डॉलर की मदद दे चुका है। ये यूएन की इस एजेंसी के मूल कार्यों के लिए है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कामों के लिए है।

हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसीके प्लेजिंग समारोह में भारत ने और आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। एजेंसी की खास गुज़ारिश पर भारत दवाईयां भी मुहैया कराएगा। भारत ने यहां एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों को सुरक्षित, वक्त पर, और लगातार मानवीय मदद की मांग की है।

कोरोना की वजह से अनाथ 51 फीसदी बच्चों का आवेदन खारिज

4,781 अनाथ बच्चों का कौन करेगा लालन-पालन...?

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया था। ऐसे बच्चों की मदद के लिए सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च किया। अब अधिकारियों की माने तो इस योजना के तहत मिले आवेदनों में से 51 फीसदी को खारिज कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 613 जिलों से कुल 9,331 आवेदन मिले थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 558 जिले के केवल 4,532 आवेदनों को स्वीकार किया गया। जबकि 4,781 को खारिज कर दिया गया। वहीं, 18 आवेदन लंबित हैं। मंत्रालय की ओर से इन आवेदनों को खारिज करने का कोई खास कारण नहीं बताया गया है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 29 मई 2021 को किया था। इसके तहत उन बच्चों को मदद मुहैया कराई जानी है, जिनके माता-पिता दोनों या वैध अभिभावकों की कोरोना महामारी से मौत हो गई हो। मोदी सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को तय करने के लिए जो कटऑफ डेट तय की, वह थी 11 मार्च 2020 से 29 मई 2023 तक। यानी इस दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या वैध अभिभावकों को खोया, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मिलने वाली सारी मदद दी जाएंगी।

राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी से सर्वाधिक आवेदन

जिन राज्यों से सबसे ज्यादा आवेदन मिले उनमें राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। यहां क्रमशः 1,553, 1,511 और 1,007 आवेदन प्राप्त हुए। महाराष्ट्र से 855, राजस्थान से 210 और उत्तर प्रदेश से 467 आवेदन स्वीकार किए गए। गौरतलब है, इस योजना का लक्ष्य बच्चों की निरंतर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इसी पोर्टल से बच्चों की सारी मदद का लेखा-जोखा भी हासिल किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों के पद भरे राष्ट्रपति ने दी दो नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर. महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। जस्टिस सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इन दोनों के नामों की सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 जुलाई को इन नियुक्तियों की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों के पद स्वीकृत हैं और इन दोनों के शपथ लेने के बाद सभी पद भर जाएंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

जस्टिस सिंह का जन्म 1 मार्च 1963 को मणिपुर के इंफाल में हुआ था। उनके पिता, दिवंगत जस्टिस एन इबोटोम्बी सिंह, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पहले एडवोकेट जनरल थे। जस्टिस सिंह ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से पहले कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की थी। उन्हें 2008 में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और 2011 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 2012 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश राय हैं। अब इन दो नई नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 पद भरे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की सूची में पान/सवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। अदालत ने प्रस्ताव को अवैध और गलत बताया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के पीठ ने की।

अदालत ने कहा,वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ पाई गई है। राज्य को इस शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता।संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने कहा कि किसी जाति,नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए संसद से बनाए गए कानून के तहत ही काम करना होगा।

बिहार सरकार ने एक जुलाई 2015 को अनुसूचित जाति सूची के लाभ को तांती-तंतवा समुदाय तक पहुंचाने के लिए अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) की सूची में तांती-तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में दूसरे समुदाय यानी पान, सवासी, पनर के साथ विलय करने की अधिसूचना जारी की थी।बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को डॉक्टर भीम राव आंबेडकर विचार मंच बिहार और आशीष रजक ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह एससी कोटे के उन पदों को वापस करे,जिन पर तांती-तांतवा समुदाय की नियुक्तियां की गई हैं। उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में वापस किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करने वाली जातियों के लिए झटका है।इस तरह की मांग देश के कई राज्यों में की जा रही है। आरक्षण के लाभ को देखते हुए कई जातियां खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने की मांग कर रही हैं। इसी तरह की मांग केवट और मल्लाह समेत 17 जातियां पिछले कई दशक से उत्तर प्रदेश में कर रही हैं।इनमें मझवार और भर जाति की परिभाषा में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकारों ने उनकी मांगों का पूरा करने की कोशिश भी कीं, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी हैं। इस तरह के प्रस्ताव को दो बार केंद्र सरकार भी नकार चुकी है।

आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ीं

चिकित्सीय प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करेगी पुलिस

पुणे (ईएमएस)। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब खबर आई है कि पुणे पुलिस पूजा खेडकर के चिकित्सीय प्रमाण पत्रों (मेडिकल सर्टिफिकेट्स) की सत्यता की जांच करेगी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का बीते दिनों ही पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर किया गया था।

महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर गलत तरीके से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने का आरोप है। जिसमें उन्होंने खुद को कई शारीरिक समस्याएं होने का दावा किया था। आईएएस पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग में अपने कई चिकित्सीय प्रमाण पत्र जमा किए थे, जिनमें से एक प्रमाण पत्र में उन्होंने आंखों में परेशानी बताई थी, जिसकी वजह से उन्होंने देखने में थोड़ी समस्या होने का दावा किया था। आईएएस अधिकारी ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित बताया था, लेकिन उनकी संपत्ति और उनके पिता की संपत्ति को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसके बाद उनके इस दावे पर भी शंका जाहिर की जा रही है।

छतीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियों की बंदरबांट

रायपुर (ईएमएस)। सीबीआई ने छतीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2020-2022 परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच में चौंकाने वाला खुलासा किया है। छतीसगढ़ सरकार के कहने पर सीबीआई ने ये मामला टेकओवर किया और केस रजिस्टर्ड किया। इससे पहले रायपुर ईओडब्ल्यू एसीबी इस मामले की जांच कर रही थी। छतीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (सीजीपीएससी) के तत्कालीन चेयरमेन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों की भर्ती की थी।

आरोप है कि इन्होंने अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर, भाई के बेटे को डिप्टी एसपी, बहन की बेटी को लेबर ऑफिसर, बहू को डिप्टी कलेक्टर, भाई की बहू को डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भर्ती किया। यह भी आरोप था इन्होंने कुछ नेताओं के बच्चों को भी डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे पद बांटें। सीबीआई तत्कालीन चेयरमेन, सेक्रेट्री, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के सरकारी आवास समेत रायपुर और भिलाई में कई जगह छापेमारी कर रही है। छतीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और अन्य सीनियर पोस्ट पर भर्ती होती है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 में आयोजित परीक्षा का परिणाम 2023 में घोषित किया गया था। 171 अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ी का आरोप लगा। अब सीबीआई ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। सीबीआई के अनुसार तत्कालीन सीजीपीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने कई रिश्तेदारों को बड़े पदों पर भर्ती कराया। टामन सिंह सोनवानी का बेटा नितेश डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। जांच में पता चला कि परीक्षा के दौरान उसने अपना उपनाम सोनवानी हटा लिया था। इसी तरह टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे साहिल का डिप्टी एसपी पद पर चयन हुआ। इसने भी परीक्षा के दौरान सोनवानी उपनाम हटा दिया था। टामन सिंह सोनवानी की बहू मतलब उसके बेटे नितेश की पत्नी निशा कोसले का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इसका चयन 2020 में हुआ था। 2020 में टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू दीपा आदिल का चयन जिला आबकारी अधिकारी के पद हुआ था। टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी सुनीता जोशी का चयन श्रम अधिकारी के पद पर हुआ। टामन सिंह सोनवानी ने यहीं तक उपकार नहीं किया। उनके सचिव के बेटे सुमित ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए।

तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमित खलको का बेटा निखिल खलको और बेटी नेहा खलको भी डिप्टी कलेक्टर बन गया। बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर पर पर चलनित हो गईं। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी की बेटी प्रज्ञा नायक भी डिप्टी कलेक्टर बनीं। इसी तरह इसी कांग्रेस नेता के ओएसडी का बेटा प्रखर नायक वित्त विभाग में अधिकारी के रूप में चयनित हुआ। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुईं। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर बने। साथ ही इनकी बेटी भूमिका कटियार भी डिप्टी कलेक्टर बनीं। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी के साढ़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरा भी डिप्टी कलेक्टर बनीं। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर बनीं। एक अन्य कांग्रेस नेता का बेटा राजेंद्र कुमार कौशिक का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ।

जन हितैषी

सरकारी धन की लूट, रिश्वत और भ्रष्टाचार का साम्राज्य

आम जनता अपना वोट देकर नेता चुनती है। अपने अधिकार नेताजी को सौंप देती है। नेताजी और अधिकारी मिलकर आम जनता के विश्वास को धोखा देते हैं। फाइलों में गरीबों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं का लाभ गरीबों को आज भी नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सरकार के राज में अभी भी अधिकारी और नेता मिलकर आम आदमी की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हर काम में दलाली करते हैं। गुंडों की फौज खड़ी कर लेते हैं, इस काम में न्यायपालिका का सहारा भी नेताओं और अधिकारियों के इस गठजोड़ द्वारा लिया जा रहा है। जिसके कारण आम जनता कराह रही है। कहने को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता के नौकर हैं। लेकिन अब जनता से मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेताओं के साथ मिलकर नौकरशाह आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लुटता आम आदमी है, उसको कानूनों के मकड़जाल में फंसा दिया जाता है। भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरों के ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मध्यप्रदेश का व्यापमं घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए नेता और अधिकारियों के गठजोड़ ने नियमों और कानून का ऐसा जाल बना दिया। जिसमें आदिवासी फंसकर फड़फड़ाते रह गए। उनकी जमीनों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया। रक्षक ही अब भक्षक बन रहे हैं। न्यायपालिका द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर समर्थ लोगों को ही न्याय दिया जा रहा है। गरीब आदमी सारे जीवन अदालतों के चक्कर लगाता है। वकीलों को पैसा देता है, उसके पास जो होता है, वह भी लुट जाता है। थक-हार के घर में बैठ जाता है, यही वर्तमान का सच है। खुलेआम अवैध शराब और मादक पदार्थ बिक रहे हैं। अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। नगर पालिका, नगर निगम और अब ग्राम पंचायतें भी आम नागरिकों पर कुछ वर्षों में टैक्स और नए-नए शुल्क लगाए जा रहे हैं। सुविधा खत्म होती जा रही हैं। पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बड़े-बड़े सपने दिखाकर चले जाते हैं। सरकारी खजाने से हर विभाग को जो राशि मिलती है। नेता और अधिकारी फाइलों पर जनहित की योजनाओं की राशि खर्च कर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अनाज भी अब फर्जी तरीके से बांटा जा रहा है। सरकार कहती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। लेकिन आधे से अधिक राशन नेताओं और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मिली भगत के कारण लूट लिया जाता है। पिछले 30-40 वर्षों में नेता और अधिकारी देवताओं की तरह पूजे जा रहे हैं। विरोध करने या अधिकार मांगने पर जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे नेताओं और सरकारी अधिकारियों का यह चरित्र बन गया है। शहरों में हाहाकार मचा है, पानी नहीं मिलता है। समय पर सफाई नहीं होती है। बिजली की कटौती कई बार होती है। अनाप-शनाप बिल भेजे जाते हैं। नेता और सरकारी अधिकारी मिलकर पहले झुग्गी बस्ती बसातें हैं। पुनर्वास के नाम पर करोड़ों रुपए की योजना बनाते हैं। गरीबों को घर नहीं मिलते, नेताओं और अधिकारियों के दलाल उस पर कब्जा कर लेते हैं, किराए पर या बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कई वर्षों से यह धंधा अनवरत रूप से चला आ रहा है। फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी जमीन के पट्टों, फर्जी संस्थाएं जहां देखो, वहीं घपले-घोटाले खुलेआम कर रही हैं। जांच के नाम पर वर्षों तक गड़बड़ियों और घोटालों को दबाकर रखा जाता है। जब लोग भूल जाते हैं, तो जांच में जिम्मेदार व्यक्ति निर्दोष करार कर दिए जाते हैं। अभी बरसात शुरू हुई है। हर शहर नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश में जगह-जगह पानी भर जाता है। रोड गड्ढों में बदल गई है। सूचना अधिकार कानून में अब जानकारी मिलना बंद हो गई है। संविधान में लोकतंत्र की जो परिभाषा लिखी है। वर्तमान में वह परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। जनता का राज होगा। विधायिका और कार्यपालिका ने मिलकर मलिक को नौकर की तरह बंधक बनाकर रखा है। आम जनता से नौकरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हर स्तर पर चौथ वसूली हो रही है। अब ऐसे संगठित गिरोह हो गए हैं, जो सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर जनता को धमकाते और डराते हैं। शासन-प्रशासन और राजनेताओं का चौथ-वसूली में संरक्षण होता है। राजाओं के शासनकाल में राजा के सैनिक गांव-गांव में जाकर लूटमार करते थे। लगभग वही स्थिति अब बन गई है। ऐसा लगता है कि सुधार के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। न्यायपालिका भी अब शासन के अधीन होकर रह गई है। न्यायपालिका से अब न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय सरकार और सरकारी अधिकारियों के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रही हैं। आम जनता में नाराजी और मायूसी देखने को मिल रही हैं। यह स्थिति धीरे-धीरे बगावत को जन्म देती है। वर्तमान शासन-प्रशासन की व्यवस्था शक्तिशाली लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह गई है। न्यायपालिका भी इन्हीं के प्रभाव में काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। ऐसी स्थिति में जनता को अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सामने आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सरकार कहती है, यदि लोगों को कष्ट होता, तो जनता सड़कों पर आती। सरकार को ऐसा लगता है, जनता के पास बहुत पैसा है। जनता पैसा खर्च कर रही है, मतलब उसके पास पैसा है। मंहगाई और बेरोजगारी का कोई असर नहीं है। सरकार का मानना है, जनता को जिस दिन कष्ट होगा। वह सड़कों पर आएगी, सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। जनता ऐसा नहीं कर रही है इसका मतलब है, सब चंगा है। चुनाव जीतना और सरकार में बने रहना ही सफलता की निशानी है। चुनाव अब जनता के वोट से नहीं प्रबंधन से जीते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता की यही दुर्दशा होनी थी। जनतंत्र से एक बार फिर हम राजतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही वर्तमान का सच है।

राजस्थान भाजपा में उठने लगे बगावत के स्वर

लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा में जमकर उठा पटक मची हुई है जो भविष्य में आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सरकारी गाड़ी व अन्य सरकारी सुविधाएं भी लौटा दी है। यहां तक की डा. किरोड़ी लाल मीणा बजट सत्र में भी विधानसभा में नहीं आने की घोषणा कर चुके हैं। डा. किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। सरकार में हो या विपक्ष में वह अपनी बात पूरी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं।

डॉ. किरोडी लाल मीणा मंत्रिमंडल के गठन के वक्त से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुरूप महत्व नहीं मिला था। जिसके चलते वह अंदर खाने नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। डॉ. किरोडी लाल मीणा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके उपरांत भी उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। कहने को तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज नहीं है और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बजट सत्र में भी विधानसभा नहीं आकर डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी खुलकर जता दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने उपेक्षा से पहले से ही दुखी है। गाहे बेगाहे अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती है। विधानसभा में भी वसुंधरा समर्थक विधायक सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को पूरी आशा थी कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर जिस प्रकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेब से पर्ची निकाल कर वसुंधरा राजे से नए मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा करवाई। उससे वसुंधरा राजे की आम जनता में काफी फजीयत हुई थी। जिसे वसुंधरा अभी तक भूल नहीं पाई है।

लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार से जहां केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है वही राजस्थान में तो भाजपा सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य सभी अग्रिम पंक्ति के नेताओं की जमकर किरकिरी हुई है। केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोक सभा सीट से महज 55711 वोटो के अंतर से जीत सके हैं। जबकि 2019 में वह 264081 व 2014 के चुनाव में 308079 वोटो के अंतर से चुनाव जीते थे। इस तरह देखे तो इस बार अर्जुन राम मेघवाल ने बहुत ही मुश्किल से चुनाव जीता है। जबकि उनके पड़ोस की श्रीगंगानगर, चुरु, झुंझनू, सीकर सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई है।

इसी तरह तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस के अनजान से प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा को 115677 वोटो से हराया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को 274440 वोटो से व 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच को 303464 वोटो से चुनाव हराया था। इस बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह का प्रभाव भी कम हुआ है। गजेंद्र सिंह के पड़ोस की बाड़मेर-जैसलमेर, नागौर, सीट पर भाजपा चुनाव हार गई है। जबकि पिछली बार यह सभी सीट भाजपा के पास थी। गजेंद्र सिंह शेखावत का शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ से चुनाव पूर्व हुआ विवाद भी खास सुर्खियों में रहा था। बाड़मेर-जैसलमेर सीट पर तो भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहें थे। उन्हें मात्र 16.99 प्रतिशत यानि 286833 वोट ही मिल पाए थे। जबकि 2019 का चुनाव कैलाश चौधरी ने 323808 वोटो से जीता था। तब उन्हें 846526 वोट मिले थे।

लोकसभा चुनाव में चूरू सीट पर भाजपा सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटे जाने से जाटों में भाजपा के प्रति काफी नाराजगी व्याप्त हो गई थी। जिसका खामियाजा उन्हें जाट बहुल अधिकांश सीटों पर हार कर चुकाना पड़ा था। पिछली बार भाजपा के पांच सांसद जाट वर्ग से थे। जबकि अबकी बार अजमेर से भागीरथ चौधरी जीत पाए हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने पुत्र के झालावाड़ संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रही थी। उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में तो शामिल किया गया था। मगर चुनाव प्रचार के लिए कहीं नहीं भेजा गया। सीकर से दो बार भाजपा सांसद रहकर पिछला चुनाव हार चुके स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने खुलकर कहा है कि यदि वसुंधरा राजे से चुनाव प्रचार करवाया जाता तो नतीजे हटकर मिल सकते थे।

झुंझुनू से भाजपा टिकट पर चुनाव में पराजित हुए शुभकरण चौधरी ने अपनी हार का कारण अग्निवीर योजना को बताया था। भाजपा के बहुत से नेताओं का मानना है कि राजस्थान से सेना में सर्वाधिक नवयुवक भर्ती होते हैं। अग्निवीर योजना आने के बाद राजस्थान के युवाओं में खासी नाराजगी व्याप्त हो रही है। कांग्रेस ने वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना बंद कर देगी। इससे बड़ी संख्या में नवयुवकों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी सभी 25 संसदीय सीटों पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सक थे। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव के दौरान व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर सके। इसी के चलते अपने गृह जिले भरतपुर की लोकसभा सीट भी हार गए। कोटा जैसी भाजपा की मजबूत सीट पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बार महज 41974 वोटो के अंतर से ही जीते हैं। जबकि पहले के चुनाव में उनकी जीत का अंतर लाखों वोटो में होता रहा था।

राजस्थान में भाजपा की सरकार बने सात महीने से अधिक का समय हो चुका है। मगर अभी भी सरकार पर मंत्रियों की पकड़ नहीं बन पाई है। अधिकारी वर्ग मंत्रियों की बातों को अधिक तवज्जो नहीं देते हैं। जिसके चलते मंत्रियों द्वारा आम जनता मे की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने से उनकी स्थिति हास्याद पद बन जाती है। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष एक ही जाती के हैं। विभिन्न निगम, बोर्ड, आयोग, मण्डलों में भी अभी तक या तो पीटे हुए मोहरों को या अधिकारियों को ही नियुक्ति दी गई है। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द वही चौकड़ी रहती है जो उनके प्रदेश महामंत्री रहते उनके साथ रहती थी। इससे आम जनता में सरकार की छवि खराब हो रही है।

अगले कुछ महीनो में प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पांच में से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन यदि भाजपा इन पांच सीटों को फिर से हार जाती है तो मुख्यमंत्री की नकारात्मक छवी बनेगी। इसलिए सरकार के समक्ष सभी पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीतना एक मजबूत चुनौती बन गई है। भाजपा यदि पांचों सीटों पर उपचुनाव में जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव की हार का गम कुछ कम होगा। वरना आने वाले समय में पार्टी आलाकमान द्वारा राजस्थान को लेकर कई बड़े निर्णय किए जाने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है। (लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा/ ईएमएस) (लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है।)

पाकिस्तान में भुट्टो का इतिहास दोहराने की तैयारी तो नहीं

पाकिस्तान में लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का सदा से यह रोना रहा है कि सेना के बूटों तले लोकतांत्रिक सरकारों के कुचले जाने के बाद मुल्क में लोकतंत्र सिर्फ सांसे लेने के लायक ही बचा रहता है। दूसरी तरफ आतंकियों द्वारा नेताओं की सरेआम हत्याओं के चलते भी पाकिस्तान में लोकतंत्र सहमा नजर आता है। यदि इनमें से कुछ बच रहता है तो साजिश के तहत बनने वाली सरकारों के फैसले लोकतंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बतलाना होगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को अचानक किस तरह से फांसी पर लटकाया गया था। पाकिस्तान के तब क्या हालात थे और किस तरह से एक चुने हुए व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा अपराधी ठहरा सदा के लिए खामोश कर दिया गया। इससे आगे बढ़ें तो देखें कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को सेना प्रमुख ने अपने दम पर कब्जे में लिया और खुद राज करते नजर आए। यही नहीं जवाब तो यह भी घटना मांगती है कि आखिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी हिमायती बेनजीर भुट्टो को सरेआम हलाक कर दिया गया। घटनाएं और भी हैं जो लोकतंत्र की जड़ में मठा डालने वाली साबित होती हैं, लेकिन यहां बात हम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े पैंचीदा मामले की कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान अब आफत में नजर आ रही है। वही इमरान जो पाकिस्तान के हीरो कहे जाते हैं और अपने जमाने के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान होने के चलते दुनियाभर में उनके चाहने वाले और शुभचिंतक मौजूद हैं। एक वह वक्त था जबकि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग क्रिकेट मैदान तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब वो सियासी गलियारे के विवादित शख्स के रुप में पहचाने जा रहे हैं और मौजूदा समय में जेल में हैं। इससे पहले वो शादियां करने और तलाक के लिए भी चर्चा में रहे हैं। पारिवारिक मामलों को यदि छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि इमरान खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि राजनीति के मैदान में भी सफलता के परचम लहरा चुके हैं और पाकिस्तान के शीर्ष प्रधानमंत्री पद को भी संभाल चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि कभी किसी ने अपना समय तो देख कर नहीं आया है, सो भविष्य में क्या होगा यह तो उन्हें भी नहीं मालूम था और आज जिस परेशानी ओर मुसीबत से वो गुजर रहे हैं, इसकी तो उन्हें भी भनक नहीं लगी होगी। वर्ना इसके बचाव और रास्ते बदलने के प्रयास तो उन्होंने जरुर ही किए होते।

दरअसल पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस बात की जानकारी मुहैया करा दी है। जिसके बाद से पाकिस्तान में इमरान और उनकी पार्टी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं आम हो चली हैं। सूचना मंत्री तरार ने 15 जुलाई के दिन कहा कि उनकी सरकार पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जाने का कारण गिनाने की जगह उन्होंने दो-टूक कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते हैं। यह सियासी पार्टी और इसकी सोच मुल्क के लिए खतरा बन गई हैं। यहां उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए यह भी कह दिया कि इस पार्टी के लोग देशविरोधी कामों में शामिल हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अपनी ही जमात के लोग अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई कैसे समझा सकता है कि आखिर लोकतंत्र वो खूबसूरत व्यवस्था है, जिसमें हिंसा और खून-खराबे के बगैर ही सरकार को बदला जा सकता है। ऐसा करते हुए सिर्फ सरकार ही नहीं बदली जाती बल्कि देश की दशा और दिशा बदलने का काम भी बहुत ही शांति के साथ कर दिया जाता है। सोच बदलती है और कार्यप्रणाली में उसे लागू करते हुए अमली जामा पहना दिया जाता है। ऐसा करते हुए लोकतांत्रिक सरकारें कभी भी डर या भय का वातावरण देश में निर्मित नहीं करती हैं, बल्कि जो काम अदालतों का होता है वो उन्हें करने देती हैं और जो काम उनका होता है यानि कानून बनाने और देश की तरक्की के रास्ते खोलने सो वो ईमानदारी से करती हैं। पाकिस्तान में इस तस्वीर को उलट कर देखने की जरुरत है, क्योंकि यहां सत्ता पाना और सत्ता के रास्ते से अपने प्रतिद्वंदी को हटाना ही सब कुछ होता है। देश और आवाम की फिकर किसे होती कहना मुश्किल है।

बहरहाल पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और पूर्व उपसभापति कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाने का महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। यदि यह सब सही साबित हो रहा है तो यकीन जानिए कि बहुत जल्द जुल्फीकार अली भुट्टा प्रसंग लोगों को एक बार फिर याद हो आएगा क्योंकि आर्टिकल 6 के तहत मामला साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। जिंदगीभर चुनाव नहीं लड़ पाने का संकट कोई बड़ा संकट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नेता मार्गदर्शक बन पार्टी को आगे बढ़ाते हुए अपने ही लोगों के जरिए अपनी नीतियों के तहत देश चलाने में सक्षम होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जननेता को सच्चा समाजसेवक होना चाहिए, तभी वह देश और आवाम का भला कर सकता है। पाकिस्तान में तो जिसे देखिए वही अपना खुद का भला करने में लगा हुआ नजर आता है। सत्ता में रहते हुए आरोप लगना आम बात है, लेकिन अपराधी ठहराए जाना और फिर विदेशों में अपने बचे हुए दिनों को काटना या उस वक्त का इंतजार करना जिसमें कि वो वापसी कर फिर सत्ता में काबिज हो सकें। इसके भी पाकिस्तान में कम उदाहरण नहीं हैं।

पाकिस्तान की मौजूदा सरकार अपने फैसले को सही साबित करने के लिए इतना तो कहती दिखती है कि पीटीआई पर कार्रवाई के लिए विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं। तरार बताते हैं कि विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई को हुए दंगे, सिफर प्रकरण और अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए यह सरकार मानती है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये सबूत ही काफी और विश्वसनीय हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है, जिसमें पीटीआई को एक राजनीतिक दल के रुप में कार्य करने की इजाजत दी गई है। इसके जवाब में सूचना मंत्री तरार का कहना था कि शहबाज सरकार ऐसे फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समीक्षा याचिका भी दायर करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इमरान खान की पार्टी राष्ट्रीय विधायिका में 20 से अधिक अतिरिक्त आरक्षित सीटों के लिए पात्र है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की गठबंधन सरकार पर सदन के भीतर दबाव बढ़ा, संभवतः अब वह दबाव और बर्दाश्त करने के लायक नहीं बची है। इसलिए इस फैसले को भी सरकार चुनौती देने की बात कह रही है। इस तरह के तमाम सवाल पाकिस्तानी मीडिया से छन-छन कर दुनियां के सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ तो देश में अचानक और अचंभित करने जैसा होने जा रहा है। अप्रत्याशित कुछ भी नहीं, लेकिन वह कैसे और कब होगा यह खास मायने अब रखता है।

अंततः पूर्व प्रधानमंत्री 71 वर्षीय इमरान खान के बारे में थोड़ा बतलाते चलें कि वो पाकिस्तान ही नहीं दुनियां के लोकप्रिय क्रिकेटर रहे हैं। उनकी शानदार कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में एकदिवसीय वर्ल्डकप जीत दुनियां के खेल जगत में देश का नाम रोशन कर दिया था। खेल के मैदान में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद इमरान राजनीति में कदम रखते हैं और 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का गठन कर जाते हैं। इसके साथ ही जनता का सहयोग मिलता है और अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान 1996 से 2023 तक पीटीआई के अध्यक्ष रहते हैं। अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करते हुए एक इतिहास रचने जैसा काम कर चुके हैं। यहां साल 2022 में वो पीएम पद से हटते हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उन पर दना-दन कई मामले दर्ज हो जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। बहरहाल इमरान खान जो फिलहाल जेल में हैं के खिलाफ सरकार ने अंतिम कदम उठाने जैसी घोषणा करके सभी का ध्यान एक बार फिर इमरान की तरफ मोड़ दिया है। देखना होगा कि पाकिस्तान में इतिहास दोहराया जाता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, क्योंकि दुनियां की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात पर यूं ही नहीं टिकी हुई हैं।

यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान एक बार फिर हिंसा और मार-काट के दौर से गुजरता हुआ दिखेगा। इसका फायदा सौ फीसद आतंकवादी अपने मंसूबों को अमली जामा पहना कर उठाएंगे ही उठाएंगे। यही नहीं पाकिस्तान से अलग होने का राग अलापने वाले संगठन और उनके समर्थक भी इस माहौल का भरपूर फायदा उठाते हुए बगावती तेवर दिखाएंगे। पाकिस्तान से अलग होने के लिए एक टांग पर खड़े बलूच और उनके समर्थक जोड़-तोड़ कर कुछ ऐसा करने की फिराक में होंगे, जिससे बांगलादेश की तरह उन्हें भी आजादी हासिल हो जाए। ऐसे में हाल ही में अफगानिस्तान से पंगा ले चुके पाकिस्तान को सीमापार से चुनौतियां मिलेंगी ही मिलेंगी। इन तमाम परेशानियों और झंझावातों से यदि लड़ने की छमता सरकार में है, तो वह अपने फैसले पर अडिग रह सकती है, वर्ना शतरंज की बाजी की तरह अपने बढ़ाए हुए गलत समय में गलत मोहरों को वापस अपने घर लाना ही समझदारी है। (लेखक- डॉ हिदायत अहमद खान / ईएमएस)

राजनीति की परिणिति : 'संविधान' पर राजनीति कितनी संवैधानिक....?

हमारे देश के संविधान के ''हीरक जयंती'' वर्ष में मौजूदा राजनेताओं ने इसे अपने 'राजनीतिक अस्त्र' के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरूआत स्वयं केन्द्र में आसीन सत्तापक्ष ने अब हर वर्ष पच्चीस जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा के साथ की है, सन् 1975 की पच्चीस जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अर्धरात्रि में अचानक पूरे देश में 'आपातकाल' लागू करने की घोषणा की थी और सारी प्रशासनिक राजनैतिक शक्तियों को अपने हाथों में लेकर प्रतिपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया था, देश में यह आपातकाल करीब बीस महीने रहा और इस दौरान इंदिरा जी ने पूरी मनमानी सरकार चलाई और सभी दण्ड-कानूनों का खुलकर दुरूपयोग किया, ऐसे आरोप लगाने में आज भी प्रतिपक्षी दल अग्रणी है।

भारतीय राजनीति में लाया गया यह चलन कुछ इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक जन्म दिवस, समृति दिवस आदि हम मनाते आ रहे है, अब शायद पहली बार ही 'हत्या दिवस' मनाने की पहल की जा रही है और आज के राजनेता संविधान की पुस्तक का उपयोग 'खिलौने' के रूप में अपनी राजनीति को जीवनदान देने के लिए कर रहे है, प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप में संविधान की पुस्तक को अपने सिर से लगाते नजर आ रहे है, तो प्रतिपक्ष के नेता 'संविधान का गुटका' (लघु पुस्तिका) अपनी जेब में रखकर उसे हर कहीं लहराते नजर आते है, अब सवाल यह है कि यह कृत्य अपने आपमें कितना संवैधानिक है, इस पर कभी प्रतिपक्ष के नेता ने गंभीर चिंतन-मनन किया है? क्या हमारे संविधान के साथ यह सलूक उचित है? क्या संविधान को हवा में लहराने वाले अपरिपक्व नेता को संविधान के निर्माण की कहानी भी पता है, कितनी मेहनत-मशक्कत के बाद हमारी संविधान सभा ने इसकी रचना की, यह उन्हें पता है? यदि यह सब उन्हें पता होता तो वे जान-बूझकर पूरे होशों-हवास में हमारे संविधान की ऐसी बेईज्जती नही करते? उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान हमारे लिए गीता-रामायण, कुरान या गुरूग्रंथ साहिब से कम नही है, जिसकी शपथ लेकर हमारी सरकार चलती है, आज चाहे मौजूदा नेता संविधान को ताक में रखकर अपनी मनमर्जी की सरकार चला रहे हो? किंतु हमारे संविधान का महत्व अपनी जगह है और उसे विश्व के अनेक देशों ने विश्व का 'सर्वश्रेष्ठ' संविधान माना है।

यद्यपि यहां यह भी बड़े दुःख के साथ कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आज हमारा संविधान भी महाभारत के पितृपुरूष 'भीष्म पितामह' की तरह ही संशोधनों की शरशैय्या पर पड़ा कराह रहा है अब तक इसे सवा सौ से अधिक संशोधनों के तीरों से बेधा गया है, हर सत्तारूढ़ दल ने अपनी सुविधानुसार संशोधनों के तीरों से इसे बेधा है, फिर भी आखिर यह है तो हमारा संविधान ही, क्या आज अपनी मौत की बांट जोह रहे, इस संविधान की हत्या दिवस मनाना उचित कहा जा सकता है? किंतु आज के राजनेता किसी की हत्या में ही अपनी राजनीति का 'नवजीवन' देख रहे है, तो इसे क्या कहा जाए?

आज एक तरफ 'विश्वगुरू' का सपना देखा जा रहा है तो दूसरी ओर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी के लिए ऐसे हथकण्डे अपनाए जा रहे है और बैचारे संविधान को मोहरा बनाया जा रहा है? अब इस स्थिति को क्या कहा जाए? ....अब तो बस गांधी जी के अंतिम शब्द 'हे-राम' ही दोहराने का विकल्प शेष बचा है?(लेखक - ओमप्रकाश मेहता/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8070

बाएँ से दाएँ

1. जनमत-4
4. सचेत,सजग-4
7. सहयात्री,संगी-5
9. रुपया,पैसा -2
11. छोटी सवारी गाड़ी-2
12. घ्राणेंद्रिय-2
13. बेकार-3
15. झुका हुआ-2
16. बसंत काल-3
17. टिड्डा-3
18. अन्वेषण,ढूंढना-2
19. जलने की प्रक्रिया-3
21. एक विदेशी शराब-2
23. कला,हुनर-2
24. मैदे की एक प्रकार की रोटी-2
25. आत्मबलिदानी-5
29. करामात-4
30. नामसूची-4

ऊपर से नीचे

1. पूजा,प्रार्थना-4
2. मार्ग,पथ-2
3. यमराज,मृत्युदेवता-2
4. स्वच्छ-2
5. दूल्हा,वरदान-2
6. द्वेष,ईर्ष्या-4
8. तमीज,तहजीब-3
10. सेंधमार-5
11. चुगली करना-5
13. देवर्षि-3
14. रसद,खाद्य सामग्री-3
18. भयानक,डरावना-4
20. अक्षर (उर्दू-3)
22. संजीव कुमार व लीना चंदावरकर की फिल्म-5
25. तेज,सत्य-2
26. ईश्वर,भगवान-2
27. रुदन,क्रंदन-2
28. मोमबत्ती(उर्दू-2)

शब्द पहेली -8069 का हल

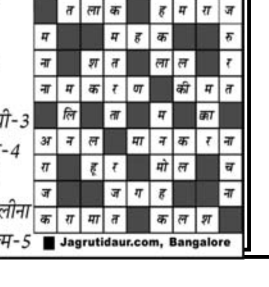

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

ऑस्ट्रिया ने दो ओवरों में 61 रन बनाकर रोमानिया को हराया

बुखारेस्ट (ईएमएस)। क्रिकेट में मैच कभी भी पलट सकता है। ऑस्ट्रिया और रोमानिया के बीच खेले गए एक मैच में ये एक बार फिर साबित हुआ है। इस मैच में ऑस्ट्रिया की क्रिकेट टीम को आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 61 रनों की कठिन चुनौती मिली थी पर उसने ये आंकड़ा एक गेंद पहले ही हासिल कर लिया। इस मैच में एक ओवर में ही 41 रन बन गये।

मैच के अंतिम दो ओवरों में ऑस्ट्रिया ने जिस प्रकार 61 रन बनाये उससे सभी हैरत में पड़ गये। इस 10-10 ओवर के इस मैच में अंत तक मेजबान रोमानियाई टीम हावी थी। ऑस्ट्रिया ने रोमानिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोमानियाई विकेटकीपर अरियान मोहम्मद के शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रिया ने 10 ओवरों में 168 रनों बना दिये।। अरियान ने 104 रन बनाये जबकि सलामी बल्लेबाज मोहम्मद मोइज ने 42 रन बनाये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रिया ने 8 ओवरों में ही 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे और वह हा के करीब जा रही थी पर आकिब इकबाल ने अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। इमरान आसिफ और आकिब इकबाल ने जमकर रन बटोरे। कप्तान इकबाल ने 19 गेंदों पर नाबाद 72 रन बना दिये जबकि इमरान आसिफ ने 22 रन नाबाद बनाए। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज करणीर सिंह ने 30 रन बनाये।

भारत के शौर्य विश्व जूनियर स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंचे

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के शौर्य बावा ह्यूस्टन में जारी विश्व जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गये हैं। शौर्य ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लो वा सर्न को 3-2 से पराजित किया। ऐसे मे अब उनका एक पदक पक्का हो गया है। शौर्य कुश कुमार के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं।

शौर्य ने 80 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पांचवें गेम में 6-9 और 7-10 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 2-11, 11-4, 10-12, 11-8, 12-10 से जीत हासिल की। अब उनकी टक्कर सेमीफाइनल में मिस्त्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया से होगी। वहीं लड़कियों के क्वार्टर फाइनल में भारत की अनाहत सिंह मिस्त्र की नादियां इल्हामामी के हाथों मिली 11-8, 11-9, 5-11, 10-12, 13-11 की हार के साथ ही बाहर हो गयी हैं।

फिटनेस टेस्ट में असफल रहे मेसी

ब्यूनस आयर्स (ईएमएस)। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनन मेसी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गये हैं। ऐसे में उनके छठे विश्वकप में खेलने पर आशंकाएं लग गयी हैं। मेसी को कोपा अमेरिका के फाइनल मुकाबले में चोट लग गयी थी जिसके बाद वह खेल से बाहर हो गये थे। खिताबी मुकाबले में उनकी टीम जीती पर वह पैर में सूजन के कारण काफी परेशान दिखे। मेसी को चोटिल होने के कारण ही पिछले साल इंटर मियामी और अर्जेंटीना के खिलाफ हुए काफी मैचों से बाहर रहना पड़ा था।

कोपा अमेरिका में भी उन्हें कई ग्रुप मैचों से उन्हें बाहर रहना पड़ा था। इक्वाडोर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में वह पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाये थे। उन्होने केवल एक गोल कनाडा के खिलाफ सेमीफाइनल में किया था। उन्हें मैच के बाद भी अपनी चोट को लेकर मीडियो को कोई जानकारी नहीं दी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वॉर्नर की वापसी से इंकार किया

सिडनी (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वॉर्नर ने टी20 विश्वकप के बाद इस प्रारुप को अलविदा कह दिया था लेकिन कहा था कि वह अगले साल होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए वापसी कर सकते हैं पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने साफ कर दिया है कि अब वार्नर के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ वॉर्नर को अंतिम बार खेलते हुए देखने की प्रशंसकों की उम्मीदें भी पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं।

वॉर्नर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 112 टेस्ट मैच, 161 एकदिवसीय और 110 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 26 शतक और 44.56 की औसत के साथ 8786 रन बनाए हैं जबकि एकदिवसीय में उन्होंने 22 शतक के साथ 6932 रन बनाए हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 70.19 का रहा है। एकदिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 97.26 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वॉर्नर ने एकदिवसीय में एक कैलेंडर ईयर में 7 शतक लगाए हैं।

वॉर्नर के नाम साल 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 335 रनों की पारी खेली थी। ये टेस्ट मैच में किसी भी ओपनर द्वारा खेली गई 5वीं सबसे बड़ी पारी है।

फुटबॉलर मुलर ने संन्यास लिया

म्यूनिख (ईएमएस)। जर्मनी के स्टार फुटबॉलर थॉमस मुलर ने खेल को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ मुलर का 14 साल से जारी खेल सफर थम गया। मुलर साल 2014 में विश्व कप विजेता जर्मनी की टीम में शामिल थे और उसके बाद से ही खेलते रह हैं। मुलर ने जर्मनी की ओर से 131 मैचों में 45 गोल दागे हैं।।

मुलर ने इस अवसर पर कहा कि अपने देश की ओर से खेलने में मुझे हमेशा ही गर्व का अनुभव हुआ है। साथ ही कहा कि हमने मिलकर जश्न मनाया और मुश्किल क्षणों में भी साथ रहे। इसी कारण मैं सभी प्रशंसकों और जर्मन टीम के अपने साथियों का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुलर ने जर्मनी की ओर से अपना अंतिम मैच यूरो 2024 के विजेता स्पेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला था। उन्होंने साल 2010 में अर्जेंटीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण करने के बाद से ही चार-चार विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप खेली हैं। वह विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं।

श्रीलंका दौरे के लिए आज हो सकती है भारतीय टीम की घोषणा

मुम्बई (ईएमएस)। श्रीलंका दौरे के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो सकती है। भारतीय टीम श्रीलंका में टी20 और एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया के नए मुख्य कोच गौतम गंभीर इस दौरे से कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि गंभीर भी टीम चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पंडया, बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। इन तीनो को ही जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया था।

इस टीम की कप्तान पंडया को मिल सकती है। वहीं सूर्यकुमार यादव उप कप्तान की जिम्मेदारी संभालंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभमन गिल ने कप्तानी की थी। पंडया, सूर्यकुमार यादव और कुलदीप के अलावा अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज की भी टीम में वापसी हो सकती है। इस टीम में सलामी बल्लेबाज के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के अलावा अभिषेक शर्मा भी अहम दावेदार हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस दौरे में एकदिवसीय सीरीज से बाहर रहने की उम्मीद है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविन्द्र जडेजा ने इस प्रारुप को अलविदा कर दिया। ऐसे में ये जगहें युवा खिलाड़ियों को मिलेंगी। ऐसे में कप्तान के तौर पर हार्दिक पंडया को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आराम दिया जा सकता है। कार्यभार प्रबंधित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर होंगे तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी में अनुभवी सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे के साथ रिंकू सिंह होंगे। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड को भी टीम में जगह मिलना तय है। गेंदबाजी में बुमराह के नहीं होने से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप के पास ही पूरी जिम्मेदारी रहेगी।

एशियाई चैम्पियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश के सोहम का चयन

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सोहम गुप्ता अब एशियाई चैम्पियनशिप में खेलते हुए नजर आयेंगे। सोहम का चयन एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ है। एशियाई चैंपियनशिप 19 से 25 जुलाई तक जॉर्डन में खेली जाएगी। सोहम अब इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। सोहम का जून में इस प्रतियोगिता के लिए हुए ट्रायल से चयन हुआ था। उसके बाद वह जयपुर में 15 दिन के अभ्यास शिविर में भी शामिल हुए। सोहम को एक दोस्त से हैंडबॉल खेलने की प्रेरणा मिली। जिसके बाद से ही वह लगातार स्टेडियम जाकर हैंडबॉल खेलने लगे। इसी के बाद में उनका चयन भारतीय खेल प्रधिकरण (साई) गुजरात के लिए हुआ। इसमें उनका खेल और बेहतर होकर निखरा। सोहम का लक्ष्य अब एशियाई चैम्पियनशिप में पदक जीतना है। उनकी सफलता से परिजनों और करीबियों में उत्साह भरा हुआ है।

शेयर बाजार रिकार्ड ऊंचाई पर बंद , सेंसेक्स 80,716 पर पहुंचा ,निफ्टी 24,613 पर बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भी तेजी रही औरये अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी होने से आया है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश से भी बाजार को बल मिला। आज कारोबार के दौरान एफएमसीजी , दूरसंचार और आईटी शेयरों में खरीददारी से भी बाजार में सकारात्मक माहौल रहा।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों परआधारित बीएसई सेंसेक्स 51.69 अंक करीब 0.06 फीसदी बढ़कर अपने अबतक के सबसेउच्च स्तर 80,716.55 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26.30 अंक तकरीबन 0.11 फीसदी बढ़कर 24,613 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 74.55 अंक करीब 0.30 फीसदी उछलकर रिकॉर्ड 24,661.25 अंक तक पहुंच गया।

बाजार में आये इस उछाल का मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की खरीदीदारी है। प्रमुख कंपनियों के तिमाही परिणाम उत्साहजनक रहने से भी बाजार ऊपर आया है।आज कारोबार के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड के शेयर नीचे आये। आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गत दिवस 2,648.78 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।

इससे पहले आज सुबह वै?श्विक बाजार से ?मिले अच्छे संकेतों की वजह से बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने तेजी के साथ शुरुआत की है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती सौदों में लगभग 170अंक बढ़कर 80,835 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी50 ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 24,650 का स्तर छू लिया, जो लगभग 75 अंक की बढ़त है। एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखा गया। ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स200 0.08 फीसदी की गिरावट में रहा, जबकि कोरिया का कोस्पी 0.07 फीसदी की बढ़त में रहा।

सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की होगी बैठक,पीएम मोदी करेंगे संबोधित

न्यूयॉर्क(ईएमएस)। सितंबर माह में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी का भाषण 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में होगा। बाद में उसी सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय किया गया है। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है।

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा करेंगे। पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया था, हालांकि सितंबर की उच्च स्तरीय बैठक में वह शामिल नहीं हुए थे। महासभा की वार्षिक बैठक में विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करते हैं और भाषणों में विकास पर टिप्पणी करते हैं, जिन पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण काम पर्दे के पीछे होता है जिसके तहत नेता दर्जनों द्विपक्षीय बैठकें करते हैं और विभिन्न फोरमों में शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया है।

बता दें कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ नेता इस वार्षिक बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी पांचवीं बार वहां उपस्थित होकर संबोधित करेंगे। इसके अलावा, 2020 में कोविड महामारी के दौरान उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था।

डोनाल्ड ट्रंप बने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। इस तरह ट्रंप तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ट्रंप ने 2016 में जीत हासिल की थी, वहीं 2020 में जो बाइडेन के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नवंबर में एक बार फिर उनका मुकाबला जो बाइडेन से होगा। ट्रंप कई महीने से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे। वह सोमवार को मिलवाउकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त करके आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो के सीनेटर जेडी वेंस को सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया।

उपराष्ट्रपति के लिए ट्रंप ने जताया बेंस पर भरोसा

ट्रंप ने एक समय अपने आलोचक रहे और बाद में करीबी सहयोगी बन गए वेंस पर भरोसा जताया है। ट्रंप ने अपने 'ट्रूथ सोशल' नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा कि लंबे विचार-विमर्श करने और कई अन्य लोगों की प्रतिभाओं पर गौर करने के बाद मैंने फैसला किया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार ग्रेट स्टेट ऑफ ओहायो के सीनेटर जेडी वेंस हैं। वेंस (39) 2016 में अपने संस्मरण 'हिलबिली एलेजी' के प्रकाशन के साथ खबरों में आए थे। उन्हें 2022 में सीनेट में चुना गया था।

गौरतलब है कि हाल में पेन्सिलवेनिया में रैली को संबोधित करते वक्त ट्रंप के ऊपर फायरिंग की गई थी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी मौत नियत कर दी गयी थी। उन्होंने इस घटना को एक विचित्र अनुभव बताया। घटना के बाद अपने पहले साक्षात्कार में 78 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने रूढ़िवादी अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्हें लगता है कि वे भाग्य या भगवान की कृपा से बच गये।

आरबीआई ने बदले बैंक धोखाधड़ी के नियम

- किसी खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्जदारों की सुनना पड़ेगी बात

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शामिल करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस में संशोधन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बैंकों से खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्जदारों की बात सुनने को कहा था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 3 संशोधित मूल दिशा-निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं। ये पूरी संचालन व्यवस्था और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी में निदेशक मंडल की भूमिका को मजबूत करते हैं। आरबीआई ने बयान में कहा ?कि मूल निर्देशों में अब स्पष्ट रूप से जरूरी है कि केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाली इकाइयां उच्चतम न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों या संस्थाओं के खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आरबीआई ने कहा ?कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया, उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिनों का उचित समय प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने किसी खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्ज लेने वाले की बातों को सुने जाने के उसके अधिकारों की वकालत की। बयान के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत कर्जदारों को नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए और उनके खाते को मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले संबंधित बैंकों को उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारतीय मूल की उषा वैंस के पति को ट्रंप ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला ऐलान किया। ट्रंप ने ओहायो के रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वैंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। जेडी वैंस ट्रंप के आलोचक रहे हैं, ऐसे में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला काफी चौंकाने वाला था। वैसे वैंस का भारत से गहरा नाता है। उन्होंने उषा वैंस ने शादी की हैं, जो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। एक लेखक, फिर रिपब्लिकन सीनेटर और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस की इस पूरी यात्रा में उनकी पत्नी उषा उनके साथ रहीं हैं। मिल्वौकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन में जब ओहायो के डेलिगेट्स अपने सीनेटर का नाम लेकर नारे लगा रहा था, तो उषा वैंस अपने सीनेटर पति के बगल में खड़ी थीं और तालियां बजा रही थीं। डोनाल्ड ट्रम्प के साथी के रूप में उनके पति का नाम वॉयस वोट से तय हुआ था। ऊषा वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। पहले उनका नाम उषा चिलुकुरी था, जो जेडी वैंस से शादी के बाद उषा वैंस बन गई हैं। वह अब भी हिन्दू धर्म का ही पालन करती हैं, जबकि उनके पति वेंस रोमन कैथलिक हैं। भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी, सैन डिएगो के एक उपनगर में पली-बढ़ीं। कॉलेज के बाद येल की कानून की डिग्री के बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट किया। येल से लॉ ग्रैजुएट बनने के करीब साल भर बाद 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी। अमेरिका के केंटकी प्रांत में दोनों ने शादी रचाई थी, जहां हिंदू पुजारी ने अनुष्ठान कराए थे। उषा और जेडी वैंस के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटों का नाम इवान और विवेक है, जबकि बेटी का नाम मिराबेल है। कुछ हफ्ते पहले तक वह बतौर वकील और ज्यूडिशियल क्लर्क के रूप में काम करती थी। वह मुंगेर टोल्स नाम की कंपनी से जुड़ी थी। हालांकि अब उन्होंने वह काम छोड़कर अपने पति के प्रचार अभियान में ही जुट गई हैं।

पाक में टेरर अटैक, 10 आतंकी हुए ढेर

पेशावर(ईएमएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 सैनिकों और 10 आतंकवादियों की जान चली गई। पाकिस्तान सेना ने मंगलवार को कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक प्रमुख सैन्य छावनी पर 10 आतंकवादियों के एक समूह के हमला कर दिया। बयान में कहा गया है कि सोमवार को 10 आतंकियों का एक समूह बन्नू छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पाक सेना ने कार्रवाई करते हुए सभी 10 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों ने इस कदम को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। आतंकवादियों की इस कोशिश में विस्फोटक से भरी एक गाड़ी सेना की छावनी की दीवार से टकरा गई। जिससे दीवार का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

मुहर्रम की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार बंद

मुंबई(ईएमएस)। मुहर्रम की छुट्टी के चलते बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। ऐसे में इस दिन शेयर मार्केट के दो एक्सचेंजों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं होगा। इस बंद से इक्विटी, डेरिवेटिव और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग सहित सभी सेगमेंट प्रभावित होंगे। गुरुवार, 18 जुलाई को बाजार में सामान्य कारोबार फिर से शुरू होगा। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 17 जुलाई को मॉर्निंग सेशन के लिए बंद रहेगा। हालांकि, यह इवनिंग सेशन के लिए शाम 5:00 बजे से 11:30 बजे या 11:55 बजे तक फिर से खुलेगा। एफएमसीजी, दूरसंचार और चुनिंदा आईटी शेयरों में लिवाली व एफआईआई प्रवाह में तेजी के बाद बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए।

सोना-चांदी की कीमतों में तेजी

- सोने का भाव 73,600, चांदी लगभग 92,850 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने और चांदी के वायदा कारोबार में मंगलवार को तेजी देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव मंगलवार को तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 73,600 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 92,850 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने के वायदा गिरावट के साथ खुले। हालांकि बाद में भाव में तेजी देखी जाने लगी। चांदी के वायदा भाव भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 186 रुपये की तेजी के साथ 73,657 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 114 रुपये की तेजी के साथ 73,585 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 201 रुपये की तेजी के साथ 92,773 रुपये पर खुला। इस समय यह 298 रुपये की तेजी के साथ 92,870 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। लेकिन बाद में इसके भाव चढ़ने लगे। कॉमेक्स पर सोना 2427.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,428.90 डॉलर प्रति औंस था। हालांकि खबर लिखे जाने के समय यह 6.10 डॉलर की तेजी के साथ 2,435 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 30.93 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव भी 30.93 डॉलर था। इस समय यह 0.13 डॉलर की तेजी के साथ 31.07 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सनकी किम जोंग ने 30 छात्रों को गोली से उड़ाया

प्योंगयान,(ईएमएस)। उत्तर कोरिया इस देश का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहां का शासक किम जोंग एक सनकी शासक है। इस बार तो उसने सनक की हद ही पार कर दी। उत्तर कोरिया की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की तानाशाह सरकार ने 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोली से उड़ा दिया। इन छात्रों पर आरोप था कि उन्होंने साउथ कोरिया में बने सीरियल को देखा था, जिन्हें कोरियन ड्रामा या के-ड्रामा कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते की बताई जा रही है

'कहते थे घर में घुस के मारेंगे, फिर जम्मू में क्या हो रहा?' आतंकी हमलों को लेकर केंद्र पर बरसे ओवैसी

नई दिल्ली : जम्मू में हाल के दिनों में बढ़े आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इन हमलों को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सिलसिलेवार हमले केंद्र सरकार की विफलता को दिखाते हैं। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी कहते थे, 'घर में घुस कर मारेंगे'। फिर यह क्या है? यह सरकार की विफलता है। वे आतंकवाद को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। डोडा में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत खतरनाक है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि डीजीपी अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि डीजीपी वहां क्या कर रहे हैं? कश्मीर बार काउंसिल के चेयरमैन पर यूएपीए लगाया है। एलओसी से काफी दूर डोडा में आज हुए हमले में आतंकी इलाके में इतने अंदर तक कैसे घुस आए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वह अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि डीजीपी को सत्ताधारी दल का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। अगर उनका इरादा है तो उन्हें भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए।

बता दें कि जम्मू के डोडा में आतंकी हमले को लेकर कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने सोमवार को कहा था कि आतंकवाद के चरम दौर में पाकिस्तान ने कश्मीर के सामाजिक जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर ली थी और यहां के स्थानीय राजनीतिक दलों ने स्वार्थ के लिए आतंकी नेताओं को बढ़ावा दिया। ओवैसी ने कहा कि हमने हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न किए हैं। चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश में मतदान प्रतिशत बहुत अधिक था। अब जब डीजीपी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है? 2021 से अब तक जम्मू में 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और 19 नागरिक मारे जा चुके हैं। हाल ही में, तीर्थयात्रियों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था।

केंद्र से सवाल करते हुए ओवैसी ने खुफिया नेटवर्क पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा आपका सूचना तंत्र कहां है? स्थानीय लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप युवाओं को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे? ओवैसी ने कहा कि सरकार कहती है कि घाटी से अनुच्छेद 370 हटा दिया है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है। जम्मू के डोडा में आतंकी हमले को लेकर कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने सोमवार को कहा था कि आतंकवाद के चरम दौर में पाकिस्तान ने कश्मीर के सामाजिक जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर ली थी और यहां के स्थानीय राजनीतिक दलों ने स्वार्थ के लिए आतंकी नेताओं को बढ़ावा दिया।

मस्जिद में गोली-बारी, 4 की मौत

मस्कट(ईएमएस)। ओमान में एक मस्जिद के पास हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मंगलवार सुबह ओमान की राजधानी मस्कट में वादी अल-कबीर मस्जिद के पास शूटिंग हुई। अलजजीरा के मुताबिक, मस्जिद में शियाओं से जुड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। ओमान की पुलिस ने कहा है कि इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। हमला किसने किया फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर हमले से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो के मुताबिक गोलीबारी शुरू होते ही मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पास में मौजूद इमाम अली मस्जिद में पनाह ली।

अफगानिस्तान में आई बाढ़ से 35 की मौत, 250 घायल

जलालाबाद (ईएमएस)। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में बारिश और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई और 250 अन्य घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि सोमवार दोपहर को आई आपदा में जलालाबाद की प्रांतीय राजधानी, सुख रोड जिले और पाकिस्तान की सीमा से लगे प्रांत के इलाके प्रभावित हुए। अधिकारी ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सोमवार सुबह नंगरहार के पड़ोसी कुनार प्रांत में भी इसी तरह की प्राकृतिक आपदा में पांच लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में मई से अब तक भारी बारिश और बाढ़ से 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते हैं आईटीआर रिटर्न

नई दिल्ली (ईएमएस)। फॉर्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अपना वार्षिक आईटीआर दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म-16 के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तब भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं।

अगर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म-16 नहीं जारी करता है, तब भी आप इनकम टैक्स विभाग की साइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस सर्टिफिकेट निकालकर अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हें। अगर आप फॉर्म-16 के बिना ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तब आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सैलरी स्लिप्स, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक से एक टीडीएस सर्टिफिकेट, हाउस रेंट और एलटीए का प्रूफ, इंवेस्टमेंट का प्रूफ और फॉर्म-26एएस या एआईएस या टीआईएस। जिस तरह फॉर्म-16 में आपकी टैक्सेबल इनकम की डिटेल होती है। उसी तरह आपको अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। इसे आप मैनुअल या कई ऑनलाइन टूल की मदद से कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स की साइट से फार्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करने पर आपको आपकी टीडीएस की डिटेल मिल जाएगी। अगर वो कटा होगा, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। आप अपने 80सी, 80डी और अन्य इंवेस्टमेंट को कैलकुलेट करके, उसे टोटल इनकम में से घटाकर अपनी टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य सोर्स से इनकम की है, तो उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाए, तब आप सामान्य आईटीआर की तरह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 6,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन (एटीएफ) पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। सोमवार को एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 16 जुलाई से लागू होंगी। भारत ने पहली बार अप्रत्याशित लाभ पर कर एक जुलाई, 2022 को लगाया था। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाते हैं। कर दरों की समीक्षा पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े की जाती है।

आईटीआर दाखिल करने में आ रही दिक्कतें, बढ़ेगी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा?

मुंबई, (ईएमएस)। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यही कारण है कि कर्मचारी आईटीआर दाखिल करने के लिए परेशान हैं। लेकिन आईटीआर फाइल करने में कई लोगों को अलग-अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने इन समस्याओं को आयकर विभाग के ध्यान में लाने की कोशिश की है। एसोसिएशन ने आयकर विभाग को एक विस्तृत पत्र लिखा है और मांग की है कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जाए. मिली जानकारी के मुताबिक आईसीएआई ने आयकर विभाग को पत्र लिखा है. इस पत्र में आईटीआर दाखिल करने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों का जिक्र किया गया है. आईसीएआई के चेयरमैन पीयूष एस छाजेड़ ने 5 जुलाई को यह पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने ई-पोर्टल फाइलिंग से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इन मुद्दों के कारण, करदाताओं को फॉर्म 26एएस/एआईएस/टीआईएस को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस पत्र में मांग की गई है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए.

- फॉर्म 26एएस/एआईएस/टीआईएस तक पहुंचने में कठिनाइयाँ

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने में आईसीएआई को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि फॉर्म 26एएस/एआईएस उपलब्ध नहीं है। टीआईएस और एआईएस के आंकड़े भी दिक्कतें बता रहे हैं. नतीजतन, आईटीआर दाखिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इनकम टैक्स के साथ-साथ फॉर्म 26एएस में भरे गए डेटा, ब्याज, टीडीएस आदि के माध्यम से प्राप्त आय में अंतर है। आंकड़ों में भिन्नता के कारण आईटीआर दाखिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

- एरर का आ रहा संदेश

करदाताओं के अनुसार आईटीआर दाखिल करते समय उन्हें एरर के संदेश मिल रहे हैं। इससे आईटीआर जमा नहीं हो रहा है.

- ओटीपी न मिलना

आईटीआर दाखिल करने के साथ-साथ अन्य पहचान के लिए भी ओटीपी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब करदाता ओटीपी विकल्प पर क्लिक करते हैं तो उन्हें ओटीपी नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप करदाता अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।

इस बीच, क्या आयकर विभाग इन कठिनाइयों के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाएगा? यह सवाल उठ रहे हैं.

एमएसपी नहीं बढ़ने से चीनी उद्योग परेशान : संघ अधिकारी

मुंबई (ईएमएस)। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि देश में चीनी उद्योग समस्याओं का सामना कर रहा है, क्योंकि केंद्र ने पांच साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कोई वृद्धि नहीं की है। अधिकारी कहा कि केंद्र सरकार के त्वरित निर्णय नहीं लेने से चीनी उद्योग में कार्यशील पूंजी में कम मुनाफा, कर्ज जैसी समस्याएं फिर से उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने का एफआरपी तीन बार बढ़ाया है, लेकिन चीनी के एमएसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी राज्य महासंघ पांच साल से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सकारात्मक रूप से इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी नीतियां चीनी उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर रही हैं। हम सिर्फ चीनी उत्पादन की लागत की मांग कर रहे हैं। हम उत्पादन लागत के रूप में कम से कम 41 रुपये (प्रति किलोग्राम) चाहते हैं। गन्ने की लागत बढ़ गई है, परिवहन लागत बढ़ गई है और मजदूरी शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन चीनी की कीमत वही है।

मुस्लिम पुलिसकर्मी रख सकते हैं दाढ़ी - मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई (ईएमएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों का देश है, दाढ़ी रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों खासतौर पर मुस्लिम कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मद्रास पुलिस गजट के अनुसार अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पुलिस अधिकारी जीवन भर दाढ़ी रखने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग में सख्त अनुशासन की जरूरत होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी कर्मी को दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया जा सकता है।

अदालत जी अब्दुल खादर इब्राहिम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इब्राहिम को 2019 में ग्रेड-द्द पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। 31 दिनों की अर्जित छुट्टी पूरी होने के बाद भी डयूटी पर नहीं आने और मद्रास पुलिस गजट के आदेश के खिलाफ दाढ़ी रखने की जांच शुरू की गई थी। जांच अधिकारी ने आरोपों को सही माना और पुलिस उपायुक्त (सशस्त्र रिजर्व) ने संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। हालांकि अपील के बाद पुलिस आयुक्त ने आदेश में संशोधन किया और वेतन वृद्धि को रोकने के समय को 3 साल से घटाकर दो साल कर दिया। जिसके बाद इब्राहिम अदालत पहुंचे थे।

सर तन से जुदा नारा लगाने के आरोपी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती और पांच अन्य बरी

अजमेर (ईएमएस)। एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती और पांच अन्य को बरी कर दिया, जिन्हें 2022 में निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को निशाना बनाते हुए सर तन से जुदा नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जून 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गौहर चिश्ती और अन्य को नूपुर शर्मा के खिलाफ अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर सर तन से जुदा नारा लगाते देखा जा सकता था। नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद पार्टी ने निलंबित कर दिया था।

दो साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए।

सरकारी वकील गुलाम नाजमी फारूकी ने कहा, जून 2022 में आरोपियों ने अजमेर शरीफ दरगाह के प्रवेश द्वार के नजदीक सर तन से जुदा का नारा लगाया था। खादिम गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी (31), फखर जमाली (42), रियाज हसन दल (47), मोइन खान (48), और नासिर खान (45) को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब अदालत ने बरी कर दिया है।

कांस्टेबल जयनारायण की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जून 2022 को वह दोपहर करीब तीन बजे डयूटी पर थे, उस वक्त अजमेर में एक जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, खादिम गौहर चिश्ती और अन्य ने अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर मौजूद करीब ढाई से तीन हजार लोगों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर पर सर तन से जुदा का नारा लगाया था। इसके बाद खादिम के खिलाफ धार्मिक स्थल पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आह्वान का मामला दर्ज किया गया था।

टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई की मेहरबानी

- कॉल ड्रॉप और मोबाइल नेटवर्क से जूझ रहे हैं उपभोक्ता

नई दिल्ली (ईएमएस)। हाल ही में देश के 362 जिलों में लोकल सर्किल का सर्वे किया गया है। पिछले 12 महीना में मोबाइल यूजर्स की सबसे बड़ी परेशानी कॉल ड्रॉप होना, और मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल नहीं मिलना है। मार्च से जून के बीच में किए गए सर्वे में 10 में से नौ लोगों ने स्वीकार किया है। बार-बार कॉल ड्रॉप होते हैं। कॉल ड्रॉप की शिकायत 91 फ़ीसदी उपभोक्ताओं ने की है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से भी उपभोक्ता जूझ रहे हैं।

कमजोर नेटवर्क के कारण कॉल ड्रॉप होने की शिकायत 41 फ़ीसदी लोगों ने की है। 30 सेकंड के अंदर ही कॉल ड्रॉप हो जाता है।

टेलीकॉम कंपनियां महीने के आधार पर शुल्क वसूल करती हैं। हाल ही में 10 से 25 फ़ीसदी तक शुल्क टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाया है। टेलीकॉम कंपनियां आज भी उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। इसके बाद भी उन्हें शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई है। ज़ब मोबाइल कंपनियां मुनाफे में है। उपभोक्ताओं को ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उल्टे जजिया कर की तरह हर माह उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल किया जा रहा है। ट्राई की स्थापना उपभोक्ताओं और टेलिकॉम कंपनियों के हितों में समन्वय बनाए रखने के लिए की गई थी। न्यायिक प्राधिकरण होते हुए इसका झुकाव टेलीकॉम कंपनियों की ओर होता है। जिसके कारण अब उपभोक्ताओं में टेलीकॉम कंपनियों के साथ-साथ ट्राई के प्रति भी नाराजी देखने को मिल रही है।

ब्रिटिश जूलॉजिस्ट को 249 साल की सजा

कैनबरा(ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया में जूलॉजी (जीव विज्ञान) के एक्सपर्ट एडम ब्रिटन को कुत्तों का रेप और हत्या करने के जुर्म में 249 साल की सजा सुनाई गई है। 52 साल का एडम मगरमच्छ का एक्सपर्ट है। उसने पिछले साल जानवरों पर जुल्म करने से जुड़े 60 आरोपों को स्वीकार कर लिया था। एडम एक ब्रिटिश नागरिक है। वह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में मौजूद अपने घर पर कुत्तों को टॉर्चर करता था। उनका रेप करने के बाद वह उनकी हत्या कर देता था। साथ ही वह ये सब रिकॉर्ड भी करता था। एडम ने कुत्तों का रेप करने के लिए एक टॉर्चर रूम भी बनाया हुआ था। एडम ने गमट्री ऑस्ट्रेलिया नाम की एक वेबसाइट के जरिए 42 कुत्ते खरीदे थे। उसने कहा था कि वह इन कुत्तों को नया घर देगा। इसके बाद उसने इन कुत्तों को एक शिपिंग कंटेनर में रखा। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2022 के बीच एडम ने 39 कुत्तों का रेप किया।

चांद पर मिली 100 मीटर लंबी गुफा...

भविष्य में वहां अंतरिक्ष यात्रियों को मिल सकती है शरण

केप केनवरल (ईएमएस)। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा का पता लगाया है जो उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां 55 वर्ष पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतरे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां ऐसी सैकड़ों और गुफाएं हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के आश्रयस्थल के रूप में किया जा सकता है।

इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली एक टीम ने सोमवार को बताया कि चंद्रमा पर अच्छी खासी बड़ी गुफा के साक्ष्य मिले हैं। यह अपोलो 11 के उतरने वाली जगह से सिर्फ 250 मील (400 किमी) दूर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में है। यह गुफा लावा टयूब (सुरंग की आकृति का ढांचा) के ढहने से बनी है जो कि वहां पाई गई 200 से अधिक अन्य गुफाओं की तरह है।

शोधकर्ताओं ने नासा के लूनार रीकानिसन्स ऑर्बिटर द्वारा जुटाए गए रडार आंकड़ों का विश्लेषण किया और इसके नतीजों की तुलना पृथ्वी पर स्थित लावा टयूब से की। इसके निष्कर्ष नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रडार के आंकड़ों से गुफा के शुरुआती बिंदु का ही पता है। उनका अनुमान है कि यह कम से कम 40 मीटर चौड़ी और 10 मीटर, संभवतः इससे भी अधिक लंबी है। ट्रेंटो विश्वविद्यालय के लियोनार्डो कैरर और लोरेंजो ब्रूजोन ने एक ईमेल में लिखा, चंद्रमा की गुफाएं 50 से अधिक वर्षों से रहस्य बनी हुई थीं। इसलिए, आखिरकार उनमें से किसी एक के बारे में पता लगाना काफी रोमांचक था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश गुफाएं चंद्रमा के प्राचीन लावा मैदानी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी इसी तरह की कुछ गुफाएं हो सकती हैं जहां इस दशक के अंत में नासा के अंतरिक्ष यात्री कदम रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बने गड्ढों में पानी जमी हुई अवस्था में मौजूद है जो पीने के साथ ही रॉकेट ईंधन के रूप में काम आ सकता है।

राज्य में चांदीपुरा वायरस ने बढ़ाई चिंता, तीन हफ्ते में सामने आए 13 मामले; अब तक 8 बच्चों की गई जान

गांधीनगर। मानसून शुरू होते ही चांदीपुरा वायरस नेगुजरात और आसपास के राज्यों में अपना सिर उठा लिया है। पिछले 3हफ्तों से कहर बरपा रहे चांदीपुरा वायरस ने गुजरात में 8बच्चों की जान ले ली है। जबकि कुछ अन्य संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जून के आखिरी हफ्ते में उत्तरी गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में चांदीपुरा वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया था। जिसके बाद अब तक राज्य में कुल13 मामले दर्ज किएजाचुके हैं। जिनमें से 8 बच्चों की मौत हो गई है।

चांदीपुरा मामले के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस जानलेवा वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित साबरकांठा जिले में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी तरह अरावली में पंजीकृत 3 संक्रमित बच्चों कीमौतहो चुकी है। जबकि महिसागर और राजकोटमेंचांदीपुरा वायरस से संक्रमित1-1मरीज की मौत हो चुकी है। इसके अलावा खेड़ा और मेहसाणा में1-1मरीज सामने आया है। जबकि अन्य दो मरीजों में एक राजस्थान और एकमध्यप्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल 5 मरीजों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस वायरस के चलते राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भी अलर्ट मोड में आ गई है।

चांदीपुरा वायरस से संक्रमित बच्चों के मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, जिससे बच्चों में पहले फ्लू जैसे लक्षण विकसित होते हैंऔरजल्द ही वे कोमामें चले जाते हैं या मर जाते हैं। इस वायरस का नाम महाराष्ट्र के एक गांव 'चांदीपुरा' के नाम पर रखा गया है। इस वायरस से पीड़ित बच्चों का पहला मामला1965 में इसी गांव में देखा गया था। आमतौर पर यह वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है।

चांदीपुरा वायरस आमतौर पर रेत मक्खियों या मच्छरों से फैलता है। रेत मक्खी मक्खी की एक प्रजाति है जो रेत और कीचड़ में पाई जाती है और बारिश के दौरान बढ़ती है। मैदानी इलाकों में भी चांदीपुरा वायरस का खतरा है क्योंकि मच्छर भी इस वायरस को फैला सकते हैं। पशु अनुसंधान से पता चलता है कि वायरस रोगी के न्यूरॉन्स (नसों) पर हमला करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन हो जाती है।

चांदीपुरा वायरस का वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। चूंकि यह वायरस खतरनाक है और इसके लक्षण एन्सेफलाइटिस (दिमागी बुखार) के समान हैं, इसलिए मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चांदीपुरा वायरस को रोकने के लिए मच्छरों और मक्खियों से बचना और स्वस्थ आहार खाना महत्वपूर्ण है। मॉनसून के दौरान मक्खियां खुले में मिलने वाले भोजन को खा जाती हैं, जिसके कारण ये खाद्य पदार्थ आपको भी इस घातक बीमारी का शिकार बना सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए साफ-सफाई और सावधानियां जरूरी हैं।

आइशर ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच भिडंत में 3लोगों की घटनास्थल पर मौत, एक गंभीर

वलसाड (ईएमएस) जिले के नानापोंढा के निकट आइशर ट्रक और पियागो ऑटो रिक्शा के बीच हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप स घायल हो गया है, जिसका पारडी के प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है जानकारी के मुताबिक वलसाड जिले के नानापोंढा के निकट नेवरी में ऑवरटेक के प्रयास में आइशर ट्रक ने पियागो ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिर्या इस हादसे में ऑटो में सवार तीन यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक यात्री बाल बाल बर्चा इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका पारडी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है उपचाराधीन ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है बताया जाता है कि घटना के वक्त ऑटो में ड्राइवर समेत 5 लोग सवार थें हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पारडी पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर्री

विरोध के बाद झुकी गुजरात सरकार, १३ मेडिकल कॉलेजों में घटाई MBBS पाठयक्रमों की फीस

अहमदाबादः कांग्रेस के तीखे विरोध के बाद गुजरात सरकार ने एमबीबीएस की सीटों की फीस में कमी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा पाठयक्रमों में प्रवेश के आकांक्षी विद्यार्थियों को राहत देते हुए एमबीबीएस पाठयक्रम के शुल्क में कमी की घोषणा की। हाल में सरकार ने इन महाविद्यालयों में शुल्क वृद्धि की थी। राज्य सरकार का शुल्क में कमी करने का फैसला विद्यार्थियों और राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। राज्य में गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी (जीएमई आरएस) के तहत संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में यह निर्णय लागू होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

गांधीनगर में संवाददाताओं से बातचीत में पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए 13 जीएमईआरएस महाविद्यालयों की 2100 एमबीबीएस सीट के लिए शुल्क घटाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कोटे के लिए मौजूदा शुल्क 5.5 लाख रुपये को घटाकर 3.75 लाख रुपये कर दिया गया है और प्रबंधन कोटे में इसे 17 लाख रुपये से घटाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो क्रमशः 80 प्रतिशत और 62.5 प्रतिशत की कटौती है। गुजरात सरकार ने 13 जीएमईआरएस चिकित्सा महाविद्यालयों में बढ़े हुए शुल्क में आंशिक कमी की घोषणा की है। मेडिकल पाठयक्रमों की फीस बढ़ाने को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस के साथ-साथ इस मुद्दे एबीवीपी ने विरोध में थी।

पटेल ने कहा कि नया शुल्क ढांचा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा। पिछले महीने राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जीएमईआरएस महाविद्यालयों के शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कोटे की सीट के लिए वार्षिक शुल्क 3.3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.5 लाख रुपये किया गया था जबकि प्रबंधन कोटे के लिए इसे नौ लाख रुपये से बढ़ाकर 17 लाख रुपये किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ँ्झ) ने शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की गुजरात इकाई ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी।

हिन्दू बच्चों को सिखाई जा रही थी नमाज, लगवाए जा रहे थे 'या हुसैन' के नारे

वीडियो वायरल होने के बाद बवाल वडोदरा में हिन्दू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश बताया है

वडोदश, १६ जुलाई । वडोदश के डभोई तालुका के कश्नाली आंगनवाड़ी का एक वीडियो वायश्ल हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को ईद मनाने औश स्कूल के समय नमाज अदा कश्ने के बाश्े में सिखाया जा श्हा है।

आंगवाड़ी केंद्रों में हिन्दू बच्चों को नमाज पढ़वाने, ईद मनाने औश या हुसैन के नाश्े लगवाने की खबश सामने आ श्ही है। जानकाशी के मुताबिक गुजशत के जामनगश औश वडोदश के आंगनवाड़ी केंद्रों से इस घटना का वीडियो वायश्ल हो श्हा है, जिसके बाद हिन्दू संगठनों ने इस पश कड़ी नाशजगी जताते हुए इसे धर्म पश्वर्तन की बड़ी साजिश बताया है।

मीडिया श्पोर्ट के मुताबिक, वडोदश के डभोई तालुका के कश्नाली आंगनवाड़ी का एक वीडियो वायश्ल हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को ईद मनाने औश स्कूल के समय नमाज अदा कश्ने के बाश्े में सिखाया जा श्हा है। वीडियो में बच्चों को सिश पश रूमाल बांधते, नमाज पढ़ना, ईद की श्स्में जैसे बिश्यानी बनाना, ईद मुबाश्क कहना औश ताजिया के दौशन ''या हुसैन'' के नाश्े लगाते दिखाया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पश वायश्ल हो श्हा है। ऐसा बताया जा श्हा है कि कश्नाली आंगनवाड़ी शिक्षिका ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पश ये तस्वीश्ें औश वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें आंगनवाड़ी सत्र के दौशन बच्चे सीख श्हे थे औश नाश्े लगा श्हे थे। शिक्षिका ने बच्चों के सिश पश रूमाल भी बांधा था।

दभोई के भाजपा विधायक शैलेश सोट्टा ने आंगनवाड़ी केंद्रों में इस तश्ह की गतिविधियों के संचालन पश चिंता जताई है। विधायक सोट्टा ने इस मामले में श्ज्य के प्राथमिक औश माध्यमिक शिक्षा मंत्री कुबेश्भाई डिंडोश, जिला विकास अधिकाशी ममताबेन हिश्पाश औश जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकाशी से इस घटना की शिकायत कश तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका आश्ोप है कि हिंदू बच्चों को त्योहाश्ों पश पाठ पढ़ाते समय नमाज पढ़ने के लिए मजबूश किया गया, जबकि ईद की नमाज पढ़ाना पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था।

विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि क्या शिक्षिका ने क्लास में इस्लामी धार्मिक प्रथाओं को शामिल कश्ने के लिए उचित मंजूशी प्राप्त की था औश क्या ये गतिविधियां शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुरूप थीं। वहीं, शिक्षिका ने कहा कि ईद, जन्माष्टमी, नवशत्रि जैसे त्योहाश्ों को पढ़ाना पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

सूरत महापौर राहत फंड से जरूरतमंदों को मिली 1.11 करोड़ रुपये की मदद

सूरत, 16 जुलाईः सूरत महानगरपालिका के महापौर राहत फंड से आज 498 जरूरतमंद मरीजों को 1.11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। गरीब और मध्यम वर्ग के इन मरीजों ने शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज करवाया था। नगर निगम के नीति नियमों के अनुसार, महापौर निधि से उन्हें वित्तीय सहायता मिली।

1 जुलाई को महापौर निधि की बैठक में 498 हितग्राहियों को 1.11 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई थी। यह महापौर निधि समिति से वित्तीय सहायता का सबसे तेज़ वितरण है। बैठक में अनुमोदन के बाद केवल 15 दिनों में सहायता राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई।

आज मंगलवार को सूरत महानगरपालिका के सरदार खंड में महापौर दक्षेशभाई मावाणी, उपमहापौर डॉ. नरेंद्रभाई पाटिल, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजनभाई पटेल, मेयर निधि समिति के सदस्यों और विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने मेयर निधि के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता चेक वितरित किए।

इस अवसर पर महापौर दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि महापौर राहत फंड जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है।

उपमहापौर डॉ. नरेंद्रभाई पाटिल ने कहा कि महापौर निधि समिति ने जरूरतमंद मरीजों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह से जरूरतमंदों की मदद जारी रहेगी।

सहायता चेक वितरण के दौरान लाभार्थियों के साथ उनके परिजन भी उपस्थित रहने पर सरदार खंड में भारी भीड जमा हो गई थी। इस लिए आज 410 लाभार्थि ही चेक ले पाए। बाकी लाभार्थियों को गुरूवार को महापौर कार्यालय से सहायता चेक दिए जायेगें।

72 साल की वृद्धा से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला

भरुच (ईएमएस) भरुच जिले के एक गांव से दुष्कर्म की स्तब्ध कर देनेवाली घटना सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि मौजूदा दौर में बच्ची ही नहीं वृद्धा भी सुरक्षित नहीं हैं भरुच के गांव में एक शख्स ने अपनी हवस मिटाने के लिए 72 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म किर्या घटना के बाद वृद्धा के प्राइवेट पार्ट से लगातार लहू बहने के चलते उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गर्या जहां उपचार के दौरान आरोपी शख्स का भांडा फूट गया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर्री जानकारी के मुताबिक भरुच जिले के एक गांव में रहनेवाले 48 वर्षीय अर्जुन हरिभाई वसावा नामक शख्स ने अपने पड़ौस में रहनेवाली 72 साल की वृद्धा को हवस का शिकार बनार्या वृद्धा का बेटा नौकरी पर और बहु मजदूरी करने गई र्थी बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद वृद्धा घर में अकेली रह गईं इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन वसावा वृद्धा के घर में घुस गया और उसके इस निर्दयतापूर्वक दुष्कर्म किया कि प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बहने लर्गा लिगातार लहू बहने के कारण वृद्धा की तबियत बिगड़ने पर उसे भरुच सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गर्या समय पर उपचार होने से वृद्धा की जान बच गई और पड़ौसी शख्स के पाप का भांडा फूट गर्या पुलिस ने आरोपी अर्जुन वसावा को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की हैं

सफल पायलट के बाद, सभी जिलों में 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार' पहल शुरू करेगी गुजरात सरकार

गांधीनगर,दि.16

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने बनासकांठा और पंचमहल में पायलट प्रोजेक्ट 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार' की सफलता के बाद अब इसे राज्य के शेष सभी जिलों में लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार की इस नई पहल के सफल प्रयोग से इन दोनों जिलों के जिला सहकारी बैंकों में सहकारी संस्थाओं और उनके सक्रिय सदस्यों द्वारा 4 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों में जमा राशि में 966 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हो गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि देश के सभी राज्यों के सहकार क्षेत्रों में आपस में समन्वय बनाकर देश में सहकार क्षेत्र में काम कर रही सहकारी संस्थाओं को एक नई ऊर्जा व नई पहचान दी जाए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकार क्षेत्र में नित नए प्रयोग और पहल किए जा रहे हैं। इसी दिशा में गुजरात सरकार ने भी दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार' पहल को लागू किया, जो बहुत ही सफल रहा है। गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा ने सहकार क्षेत्र की उपलब्धियों के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा, ''मजबूत सहकारी क्षेत्र ''विकसित गुजरात'' की नींव में मजबूत स्तंभ साबित हो सकता है, जो हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ''विकसित भारतॅ2047'' को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। ''

इस पहल का उद्देश्य जिला और राज्य सहकारी बैंकों के तत्वावधान में उनके बैंक खातों और जमा राशियों को केंद्रीकृत करके गुजरात की हजारों सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसमें सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में संचालित मौजूदा बैंक खातों को समेकित कर उन्हें एक केंद्रीकृत जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत लाया गया है। सहकारी संस्थाओं की सामूहिक पूंजी को एक केंद्रीकृत बैंक के अंतर्गत समेकित करने पर कई महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर, केंद्रीयकृत सहाकारी बैंक की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सहकारी समितियों के बीच फाइनांशियल लिक्विडीटी बढ़ी है, जिससे लोन संबंधी आवश्यकताओं व मांग को अब आसानी से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही, इस पहल से अब यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सहकारी संस्थाओं की सामूहिक पूंजी अन्य सहकारी संस्थाओं के भी उपयोग में लाई जा सके।

कौन होगा गुजरात भाजपा का अगला अध्यक्ष? पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित ये हैं प्रमुख दावेदार

गांधीनगर,दि.16

लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात की राजनीति में सबकी नजर पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष पर टिकी है। भाजपा के नये अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के चेहरे की तलाश है। केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद गुजरात से सांसद सी आर पाटिल (ऍ ईॅत) ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जताई, उसके बाद से राज्य में भाजपा के नये कप्तान को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं पार्टी अध्यक्ष पाटिल की अगुवाई में भाजपा ने रिकार्ड 156 सीट जीत ली, इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पांचों सीट भाजपा के खाते में आ गई।

पटेल-पाटिल की जोडी के इस कमाल केबाद सेराज्य भाजपा पूरे उत्साह में है, लेकिन लोकसभा की सभी 26 सीट पर तीसरी बार जीत हासिल नहीं कर पाने का मलाल पाटिल समेत पूरी भाजपा को है। कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकोर ने बनासकांठा सीट भाजपा से छीन ली थी। चूंकि, मुख्यमंत्री पद पर पाटीदार समुदाय के नेता हैं इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए राज्य के ओबीसी चेहरे की तलाश की जा रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं खेडा से तीसरी बार सांसद चुने गये देवुसिंह चौहाण गुजरात भाजपा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार में मंत्री जगदीश पंचाल एवं पूर्व मंत्री तथा सूरत से विधायक पूर्णेश मोदी का नामभी इस पद के लिए चल रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद गुजरातसे सांसद सी आर पाटिल ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जताई उसके बाद से राज्य में भाजपा के नये कप्तान को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। देवुसिंह चौहाण गुजरात भाजपा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

भारतीय रेल ने ''रेलवे के लिए स्टार्टअप्स'' पहल के साथ इनोवेशन को बढ़ावा दिया

नवाचारों के माध्यम से रेलवे परिचालन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने 13 जून, 2022 को ''रेलवे के लिए स्टार्टअप'' पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय स्टार्टअप, एमएसएमई, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संगठनों/संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और उद्यमियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

इस पहल के तहत भारतीय रेल इनोवेशन पोर्टल को **https:// innovation. indiån rail-ways .gov.in/** पर भी लाइव कर दिया गया है। जुलाई 2024 तक, इनोवेशन में लगी कुल 1942 संस्थाओं ने भारतीय रेलवे के इनोवेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें स्टार्टअप, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, एमएसएमई, अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि शामिल हैं।

रेल मंत्रालय ने नवाचार नीति के विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यशालाएं/बैठकें/वार्ता/वीसी का आयोजन किया है, जिसके परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स/इनोवेटर्स अच्छी भागीदारी हुई है।

रेल मंत्रालय को अब तक इनोवेशन पोर्टल पर खोले गए 28 समस्या विवरणों के लिए कुल 423 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक 15 समस्या विवरणों के लिए कुल 23 नवाचार परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। 23 पुरस्कृत नवाचार परियोजनाओं की लागत लगभग 43.87 करोड़ रुपये है, जिसमें पात्र संस्थाओं को रेलवे के अनुदान का हिस्सा लगभग 10.52 करोड़ रुपये है।

शराब तस्करी में फरार निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी गिरफ्तार, गुजरात ATS ने सुरेंद्र नगर से पकड़ा

अहमदाबादः गुजरात पुलिस की निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी को एटीएस ने अरेस्ट कर लिया है। कच्छ में शराब तस्कर के साथ पकड़ने जाने के बाद नीता चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। एक मामले में बेल मिलने के बाद नीता चौधरी फरार हो गई थी। इसका खुलासा तब हुआ था जब सेशन कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। इसके बाद कच्छ जिला पुलिस के साथ एसओजी और लोकल क्राइम ब्रांच नीता चौधरी की खोजबीन कर रही थी। आखिर में गुजरात एटीएस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल नीता चौधरी को खोज निकाला। नीता चौधरी ने गिफ्तारी से बचने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, हालांकि याचिका के सूचीबद्ध होने से पहले एटीएस ने नीता चौधरी को पकड़ा लिया। नीता चौधरी को युवराज सिंह जडेजा नाम के एक बूटलेगर (शराब तस्कर) के साथ अरेस्ट किया गया था।

कच्छ पूर्वी जिला पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद भचाऊ थाने में नीता चौधरी के खिलाफ आईपीसी 307 और निषेधाज्ञा के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए थे। नीता चौधरी को युवराज सिंह जाडेजा नाम के एक लिस्टेड बूटलेगर के साथ पकड़ा गया था। निचली अदालत ने नीता चौधरी को 307 के अपराध में जमानत दे दी। इसमें उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपनी थार पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। 307 के अपराध में निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद भचाऊ पुलिस ने सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की। गुजरात के कच्छ जिले में शराब तस्कर के साथ पकड़ी गई नीता चौधरी के फरार होने के बाद एटीएस ने खोज निकाला है। गुजरात एटीएस ने नीता चौधरी को सुरेंद्र नगर जिले अरेस्ट किया है। नीता चौधरी निचली अदालत से बेल मिलने पर फरार हो गई थीं।

निचली अदालत से मिली जमानत को रद्द करने की अर्जी दी गयी थी। निचली अदालत से मिली जमानत को सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कच्छ पूर्वी पुलिस के अरेस्ट करने के बाद नीता चौधरी की हाईप्रोफाइल लाइफ स्टाइल सामने आई थी। इसके बाद सवाल खड़े हुए थे उनके रवैए पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। फरार होने के बाद गुजरात पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। गुजरात में शराबबंदी को लागू रखने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। पुलिस कांस्टेबल के शराब तस्कर के साथ पकड़े जाने पर सवालिया निशान लगे थे। इंस्टाग्राम पर नीता चौधरी के काफी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल वाले वीडियो मौजूद हैं। नीता चौधरी बनासकांठा जिले के पालनपुर से ताल्लुक रखती हैं।

महानिदेशक /रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने किया पश्चिम रेलवे मुख्यालय का दौरा

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने 15 एवं 16 जुलाई, 2024 को चर्चगेट, मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का महत्वपूर्ण दौरा किया। श्री यादव ने अपने आधिकारिक दौरे के दौरान पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार मिश्र से मुलाकात की और प्रमुख विभागाध्यक्षों से बातचीत की। श्री यादव ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और साथ ही आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक संगोष्ठी भी आयोजित की।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस यात्रा के दौरान, श्री मनोज यादव, महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 15 जुलाई, 2024 को पश्चिम रेलवे पर नए आरपीएफ बैरकों और आरपीएफ कार्यालय का ई-उद्घाटन किया। ये नई सुविधाएं बल के बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को बढ़ाएंगी। श्री यादव ने यात्रियों के सामान की चोरी को रोकने के उद्देश्य से जन जागरूकता वीडियो की एक श्रृंखला भी लॉन्च की। महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए चल रही और भविष्य की पहलों पर चर्चा करने के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और विभिन्न विभागों के प्रधान मुख्य विभागाध्यक्षों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेन में यात्रा करके आरपीएफ थाना-दादर का दौरा किया और बुनियादी स्तर पर जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया।

16 जुलाई, 2024 को श्री यादव ने मुंबई क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 'सुरक्षा सम्मेलन' आयोजित किया। इस संगोष्ठी का आयोजन श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा, आईजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/पश्चिम रेलवे और श्री एस.एन. चौधरी, आईजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ मध्य रेलवे की उपस्थिति में किया गया। श्री यादव ने कर्मचारियों की शिकायतों को सुना और विभिन्न मुद्दों और मामलों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कर्मचारियों को ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखने, अपने कर्तव्यों में सतर्क रहने और यात्रियों के प्रति विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

श्री अभिषेक ने कहा कि महानिदेशक /रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का यह दौरा पश्चिम रेलवे के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह यात्री सुरक्षा और उत्कृष्ट सेवा के प्रति आरपीएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य

ई-निविदा सूचना सं : DRM-BRC 069 of 2024-25 भारत के राष्ट्रपति के लिए ओर उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी), पश्चिम रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा संख्या :** DRM BRC 069 of 2024-25 **कार्य का नाम :** वडोदरा (पी):- प्लेटफॉर्म संख्या 01 से 05 की प्लेटफॉर्म सतह की मरम्मत, प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 16 पर टरशियरी स्टेशन नाम बोर्ड उपलब्ध कराना, मौजूदा पार्सल कार्यालय ड्रेनेज लाइन को वीएमसी की ड्रेनेज लाइन से फिर से जोड़ना और मौजूदा हाइड्रेंट पाइपलाइन और मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत और स्थानांतरण। **कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में) :** ₹90,88,420.90 **जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा (रुपये में) :** ₹1,81,800.00 **निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय :** निविदा 02.08.2024 को 15.00 बजे से पहले जमा की जाएगी और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जाएगी। **वेबसाइट विवरण और नोटिस का स्थान जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता जहां से निविदा फॉर्म खरीदा जा सकता है :** मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 **वेबसाइट :** www.ireps.gov.in 124

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

अनंत अंबानी के शादी समारोह में बम की धमकी देनेवाला शख्स वडोदरा से गिरफ्तार

वडोदरा (ईएमएस) अंबानी परिवार के छोटे अनंत अंबानी के शादी समारोह में बम की धमकी देनेवाले एक शख्स को मुंबई पुलिस ने वडोदरा से गिरफ्तार कर लिर्या गिरफ्तार शख्स को लेकर पुलिस मुंबई रवाना हो गई हैं बता दें कि 12 जुलाई 2024 को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी हुई र्थी मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर हुए शादी समारोह के दौरान बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गईं मुंबई पुलिस ने जिस एक्स हैंडल से धमकी दी गई थी उसकी जांच शुरू कर र्दी इस पोस्ट में लिखा था 'अंबानी की शादी में एक बर्म' पोस्ट में आगे लिखा गया था 'मेरे दिमाग में एक बहुत ही शर्मनाक विचार आर्या अगर अंबानी की शादी में बम जाए तो आधी दुनिया तहस नहस हो जाएर्गी अनेक अरब डॉलर मात्र एक पिन कोड में....' इस संदर्भ में पुलिस ने कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं की लेकिन गहन जांच शुरू कर र्दी जांच करने पर इसका कनैक्शन गुजरात कनैक्शन निकर्ला मुंबई पुलिस ने वडोदरा के आजवा रोड स्थित सुवर्ण लक्ष्मी एपार्टमेंट से विरल कल्पेशभाई आसरा को गिरफ्तार कर लिर्या वडोदरा की बापोद पुलिस को साथ में रखकर मुंबई पुलिस ने यह कार्यवाही र्की फिलहाल विरल आसरा को लेकर पुलिस मुंबई रवाना हो गई हैं

एनसीएलटी ने गुजरात के 3400 करोड़ के वेल्यु वाले वाडीलाल ग्रुप के बंटवारे को दी मंजूरी

अहमदाबाद (ईएमएस) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुजरात के रु. 3400 करोड़ की वेल्यु वाले वाडीलाल ग्रुप के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि 1907 में वाडीलाल गांधी ने हाथ से चलने वाली मशीन के साथ पारंपरिक कोठी पद्धति का उपयोग करके अपनी पहली आइसक्रीम बनाई। बाद में उनके बेटे रणछोड़लाल वाडीलाल गांधी 1926 में आइसक्रीम पार्लर शुरू किए, और होम डिलीवरी की पेशकश शुरू की। वाडीलाल ग्रुप भारत की अग्रणी खाद्य निर्माण कंपनियों में से एक है। करीब 117 साल पुराने वाडीलाल ग्रुप में बंटवारे को लेकर पिछले कई सालों से आंतरिक विवाद चल रहा र्था वाडीलाल परिवार के वीरेंद्र गांधी ने आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों ने कंपनी से अवैध रूप से पैसे निकाले। यह भी आरोप लगाया गया कि समूह के पैसे का इस्तेमाल ऋण देने के नाम पर व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। हालांकि अब एनसीएलटी ने आखिरकार वाडीलाल ग्रुप के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने पारिवारिक कंपनी कानून के सिद्धांतों को लागू करते हुए आदेश पारित किया। इस मंजूरी से वाडीलाल समूह के बंटवारे को लेकर वर्षों से चला आ रहा आंतरिक विवाद खत्म हो गया है। इस मामले में एनसीएलटी ने 18 बिंदुओं के फैसले में बंटवारे की इजाजत दे दी हैं एनसीएलटी ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने लगातार आवेदन देकर कोर्ट और सरकारी तंत्र को परेशान किर्या इसलिए ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को 10-10 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया हैं

नाबालिग से अश्लील हरकत करता अधेड़ पहुंचा सलाखों के पीछे

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर के पूर्वी क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई हैं 59 वर्षीय अधेड़ शख्स ने मौके का फायदा उठाकर लड़की के साथ अश्लील हरकत र्की लिड़की के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की हैं जानकारी के मुताबिक पूर्वी अहमदाबाद के कृष्णनगर पुलिस थानान्तर्गत सोसायटी में रहनेवाली 11 वर्षीय नाबालिग लड़की गत 5 जुलाई को टयूशन से छूटकर अपने घर लौट रही र्थी उस वक्त सोसायटी के नुक्कड़ पर बैठे 59 वर्षीय अधेड़ ने लड़की को अकेला देख उसे पकड़ लिया और शारीरिक छेड़छाड़ र्की अधेड़ की हरकत से स्तब्ध लड़की अपने घर पहुंची और माता-पिता को इस बारे में बता दिर्या

पश्चिम रेलवे विशेष ट्रेन के फेरे बढ़ाएगी

ट्रेन संख्या	कहाँ से	कहाँ तक	सर्विस के दिन	विस्तारित किया
09063	वापी	दानापुर	मंगल, शुक्र, शनि	31.12.2024
09064	दानापुर	भेस्तान	रविवार	02.01.2025

ट्रेन नंबर 09063 की विस्तारित यात्राओं की बुकिंग पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुली है। ठहराव के समय और संयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया **www.enquiry. Indianrail.gov.in** पर जा सकते हैं।

उक्त ट्रेन विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी.

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फ़ॉलो करें : X.com/WesternRly

PLEASE CARRY ORIGINAL ID PROOF FOR ALL RESERVED TICKETS

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96